रायपुर

गुरुवार 15 अक्टूबर 2026

वर्ष-07, अंक-287

पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com

Website: www.eksatbulletin.in

पायलट ने गलती से भेजा हाईजैक कोड, जयपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

सूत्रों के हवाले से खबर, पायलट ने गलती से आपातकाल वाला कोड भेजा था।

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

जयपुर एयरपोर्ट पर हाईजैक अलर्ट के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रहे विमान के पायलट ने कुछ सेकेंड के लिए स्क्वाक-7500 कोड घोषित किया था। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक होने के अलर्ट के बाद हड़कंप मच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रहा था। जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को विमान को लेकर अलर्ट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं।सूत्रों के हवाले से खबर, पायलट ने गलती से आपातकाल वाला कोड भेजा था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में सभी पैसेंजर्स को डीबोर्ड किया गया है। सभी पैसेंजर्स को टर्मिनल में बैठाया गया है। विमान को



आइसोलेशन वे पर लाया गया है।बताया जा रहा है कि विमान के पायलट ने कुछ सेकेंड के लिए स्क्वाक-7500 कोड घोषित किया था। विमानन क्षेत्र में स्क्वाक-7500 का इस्तेमाल हाईजैक या विमान पर अवैध कब्जे की स्थिति का संकेत देने के लिए किया जाता है। इसी अलर्ट के बाद विमान को जयपुर की ओर डायवर्ट कर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9:45 बजे विमान को जयपुर एयरपोर्ट के आइसोलेशन वे पर ले जाया गया। सुरक्षा संबंधी आपात स्थितियों में विमान को आइसोलेशन वे पर रखा जाता है, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच कर सकें और अन्य विमानों से उसे अलग रखा जा सके। फिलहाल अलर्ट की वजह और पायलट की ओर से स्क्वाक-7500 कोड घोषित किए जाने के कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

तेल अवीव में भी विमान हाईजैक अलर्ट से मचा था हड़कंप

इससे पहले 30 सितंबर 2026 को दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 से भी हाईजैक अलर्ट आया था। बोइंग 737 मैक्स विमान ने पहले इमरजेंसी कोड 7700 और फिर कुछ समय के लिए स्क्वाक-7500 जारी किया। 7500 कोड विमान में हाईजैक या अवैध हस्तक्षेप की आशंका का संकेत देता है। इसके बाद विमान का रास्ता बदला गया और सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।इस घटना में विमान के ओमानी को-पायलट पर पायलट पर हमला करने और विमान को तेल अवीव एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराने की कोशिश करने का आरोप है। विमान की ऊंचाई में तेजी से गिरावट आई और ने हस्तक्षेप किया। विमान को सुरक्षित तबुक में उतारा गया।

न्यूज इन शॉर्ट

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की नहीं होगी सीबीआई जांच



नई दिल्ली। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतका के शव के अभाव में अब घटना की दोबारा जांच नहीं की जा सकती है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने बेटी की मौत को आत्महत्या के बजाय हत्या बताया था। साथ ही मामले की CBI जांच कराने या दोबारा जांच के आदेश देने की मांग की थी। सौरभ तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

अमेठी में जो अपने दम पर चुनाव तक नहीं लड़ सकता, वो शहंशाह बनने चला



नई दिल्ली। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी में सपा और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी की हार तय है। वहीं राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, जो बिना किसी के सहारे अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ पाते, वो अब देश की राजधानी में लगभग 14 राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर रहे हैं।BJP नेता स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची हैं। उनकी मौजूदगी में आज समाजवादी पार्टी के तीन नेताओं- अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने बीजेपी जॉइन की। इसके बाद स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बात करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी इस बात की गवाह है कि राहुल गांधी कभी भी दूसरे राजनीतिक दलों के सहारे के बिना खुद अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पाए।

सऊदी अरब ने बदल दिया वॉर गेम, भीषण स्ट्राइक में अबतक 950 हूती मारे गए, सना पर भी स्ट्राइक!



नई दिल्ली। सऊदी अरब समर्थित यमन की सेना ने हूती विद्रोहियों के गढ़ सना पर मिसाइलों से हमला किया है। कुछ ही देर पहले यमन की सरकारी सेना ने इसकी चेतावनी दी थी। ताजा अपडेट में सना में ऑयल टारगेट को निशाना बनाया गया है। हूतियों ने कहा है कि इस हमले काकड़ा और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों का प्रहार जारी है। इस बार हूतियों ने यमन में सरकारी सेना को निशाना बनाकर ताइज शहर पर हमला किया है। इस हमले में 5 लोग मारे गए हैं। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है, इसके अलावा दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच यहां स्थिति तेजी से बिगड़ रही है।

जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चिकित्सक, दवाइयां और जांच सुविधाएं रहें उपलब्ध

सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

संवाददाता ➤ रायपुर

रकों के जीवन और परिवार की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता पड़ने पर समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार, आवश्यक दवाइयां, जांच और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ सेवाओं की गुणवत्ता और अंतिम व्यक्ति तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, संचालनालय आयुष एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत संचालित योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।



मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का लगातार विस्तार हुआ है। अनेक अच्छे अस्पताल और चिकित्सा संस्थान विकसित हुए हैं। अब जहां चिकित्सकों, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सा उपकरणों अथवा जांच सुविधाओं की कमी है, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के साथ दूर किया जाए। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो और उनका अधिकतम लाभ मरीजों तक पहुंचे।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की बढ़ती आबादी और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं, जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाए। इसी आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार और आवश्यक सुविधाओं के विकास की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में आवश्यकता के अनुरूप बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार करने और नवगठित जिलों में जरूरी चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता से विकसित करने के निर्देश दिए।

री-काउंटिंग की रिकॉर्डिंग न मिलने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को दिया अल्टीमेटम

री-काउंटिंग की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया और ऐसा न होने पर प्रतिकूल निष्कर्ष की चेतावनी दी।चुनावी प्रक्रिया में रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा और बीजेपी के डीएन जीवराजा के बीच चुनावी विवाद की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि री-काउंटिंग यानी दोबारा मतगणना की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग अपने रिकॉर्ड के खोने की बात कैसे कह सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अगली सुनवाई पर उपलब्ध सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वह यह कैसे कह सकता है कि उसके पास संबंधित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनाव कराना आयोग का मुख्य काम है और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों का सुरक्षित रहना बेहद महत्वपूर्ण है।



'हल्के में नहीं लिया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस जवाब पर भी नाराजगी जताई कि रिकॉर्ड खोजने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने सवाल किया कि जब संबंधित रिकॉर्ड चुने गए उम्मीदवार को दिया गया था, तो फिर उसके सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया से

पैसों से मंदिर में क्यों लगवाई रेलिंग

एक टाइम खाना खाकर भीख से जुटाए 17 लाख

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

आम तौर पर भीख मांगकर जो पैसे प्राप्त होते हैं, उससे एक बिखारी अपना जीवन यापन करता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि भीख मांगे वाला शख्स भीख में मांगे हुए पैसों को मंदिर के विकास में लगा दे? जाहिर है आपका जवाब ना में ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक शख्स ने भीख मांगकर जमा किए गए 17 लाख रुपयों को मंदिर के विकास में लगा दिया।शख्स में मंदिर में रेलिंग लगवाई, ताकि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को समस्या न हो। ये कहानी है ।



श्रद्धालुओं को होने वाली कठिनाइयों को देखा

शिवराम रेड्डीयार ने मंदिर के विकास में भीख में मांगे पैसे लगाकर एक महान मानवतावादी के रूप में ख्याति अर्जित की है। दरअसल, उन्होंने त्रिपुरसुंदरी देवी मंदिर में त्योहारों और भीड़भाड़ के समय श्रद्धालुओं को होने वाली कठिनाइयों को देखा।

छठ तक नहीं बदलेगा ट्रेनों का प्लेटफॉर्म,

बिना टिकट स्टेशन में एंट्री बंद; भीड़ पर रेलवे का फैसला

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

रेलवे ने त्योहारों पर भीड़ प्रबंधन के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इसमें दिवाली और छठ तक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्टेशनों में बिना टिकट एंट्री बंद कर दी गई है।त्यौहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों पर संभावित भीड़ और अचानक ट्रेनों का प्लेटफार्म बदलने से मचने वाली अफरा-तफरी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी स्टेशन मास्टरों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें साफ तौर पर कहा है कि दिवाली और छठ तक ट्रेनों के प्लेटफार्म में कोई बदलाव नहीं होगा।



स्टेशनों पर बढ़ाई यात्री सुविधा

पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर, छपरा, वाराणसी, लखनऊ समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में इजाफा किया है। कोशिश की गई है कि ट्रेनों के प्लेटफार्म पर आने तक यात्री वेटिंग एरिया व विश्राम स्थलों पर रहें। इसके लिए इन स्टेशनों पर रेलवे विश्राम स्थल की व्यवस्था कराई गई है।

कारोबारियों को परेशान करना उचित नहीं-सीएम

नई दिल्ली। कांग्रेस ने 2002 में एसआईआर पर सवाल क्यों नहीं उठायाज सीएम रेखा गुप्ता का निशाना, कहा- जहां सत्ता नहीं मिलती वहीं परेशानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता न मिलने पर हंगामा कर रही है। ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित हैं, जिससे आम जनता और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।दिल्ली में स्क्रैक के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और प्रदर्शनकारियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब साल 2002 में दिल्ली में स्क्रैकहुआ था, तब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई? मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल तब परेशानी होती है, जब उसे सत्ता नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होतीं,।

तमिलनाडु में उसे हर साल अनुमति देने से क्यों रोका जा रहा है

आतंक प्रभावित कश्मीर में आरएसएस को मार्च की इजाजत तो तमिलनाडु में रोक क्यों: हाई कोर्ट

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति का मामला मद्रास ाष्ट पहुंच गया है। अदालत ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में मार्च हो सकता है, तो तमिलनाडु में अनुमति क्यों नहीं मिल रही?

तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके रूट मार्च को अनुमति देने का मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य पुलिस से सवाल किया कि जब स्क्रस्स जम्मू-कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में भी मार्च निकाल सकता है, तो तमिलनाडु में उसे हर साल अनुमति देने से क्यों रोका जा रहा है।



हर साल सामने आता है मार्च की अनुमति का मुद्दा

लाइव लॉ के मुताबिक, RSS की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन एल राजा ने कहा कि संगठन को हर साल अनुमति के लिए अदालत जाना पड़ता है। यह मामला सिर्फ स्क्रस्स के मार्च की अनुमति तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जुलूसों, कानून-व्यवस्था और पुलिस की अनुमति देने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है स्क्रस्स की ओर से अदालत में कहा गया कि संगठन को हर साल मार्च निकालने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। के नियमों का मुद्दा उठाया।

'ये सरकार किसी भी जुलूस के खिलाफ है'

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन ने सवाल किया 'अगर वे जम्मू और कश्मीर जैसी आतंकवाद प्रभावित जगह पर मार्च निकाल सकते हैं, तो तमिलनाडु पुलिस हर साल उन्हें अनुमति क्यों नहीं देती' उन्होंने कहा कि अभी की सरकार किसी भी तरह के जुलूस की परमिशन देने से इनकार रह रही है। इसी वजह से उन्हें अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'यह सरकार किसी भी जुलूस के खिलाफ है।

न्यूज इन शॉर्ट



जिले में 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होंगे वित्तीय समावेशन शिविर

प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा सहित अटल पेंशन योजना से पात्र हितग्राहियों को किया जाएगा लाभान्वित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार जिले में 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर वित्तीय समावेशन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना तथा केंद्र सरकार की प्रमुख वित्तीय सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है।

जिला अग्रणी बैंक कार्यालय पेंड्रारोड द्वारा जारी पत्र के अनुसार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों के जनधन खाते खोलने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही निष्क्रिय जनधन खातों को सक्रिय करने, आधार सीडिंग, लंबित केवाईसी एवं सी-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने तथा बचत खातों में नामांकन संबंधी जानकारी अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शिविरों में नागरिकों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं के लाभ, बैंकिंग सुविधाओं एवं डिजिटल लेनदेन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में भी जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्र को कम से कम एक शिविर से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिला अग्रणी बैंक कार्यालय ने सभी बैंक शाखाओं को बैंक मित्रों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। जिले के नागरिकों से इन शिविरों में पहुंचकर बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड-03 एवं भृत्य पदों की पात्र-अपात्र सूची जारी

दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड-03 एवं भृत्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों की जांच के बाद तैयार पात्र-अपात्र सूची कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। जारी सूची के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति होने पर वे 29 अक्टूबर तक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, कुरियर अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेजों सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी भी दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

देवगुड़ी निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, सरपंच-सचिव और इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत, स्वीकृत राशि और निर्माण कार्य की जांच कराने की उठाई मांग

महेंद्र शुक्ला ➤ एमसीबी

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की ग्राम पंचायत धनवारडीह-डांड में देवगुड़ी निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से करते हुए सरपंच, सचिव एवं संबंधित इंजीनियर की भूमिका की जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2025 में देवगुड़ी शेड निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृत राशि प्रदान की गई थी। आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया और स्वीकृत राशि के उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुराने निर्माण को ही देवगुड़ी निर्माण बताने का



आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर देवगुड़ी शेड का निर्माण होना बताया जा रहा है, वहां पहले से ही ग्रामीणों द्वारा निर्मित एक मंदिर मौजूद है। शिकायत में कहा गया है कि मंदिर की पुरानी दीवारों, फर्श और अन्य संरचनाओं का उल्लेख करते हुए नए निर्माण कार्य की वास्तविकता पर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, निर्माण कार्य के लिए तैयार प्राक्कलन और मौके पर मौजूद संरचना के बीच अंतर होने की आशंका है। ऐसे में निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।

सरपंच, सचिव और इंजीनियर की भूमिका पर सवाल

शिकायत में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और संबंधित इंजीनियर पर निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने तथा शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता, खर्च की गई राशि और स्वीकृत प्राक्कलन की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

दस्तावेजों के आधार पर जांच की मांग

शिकायत में निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलन, माप पुस्तिका (एमबी), निरीक्षण प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भुगतान संबंधी दस्तावेज और निर्माण स्थल की तस्वीरों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से स्वयं स्थल का निरीक्षण कराने और मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब देखना होगा कि जिला प्रशासन मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। यदि निर्माण कार्य में अनियमितता हुई है, तो जांच के जरिए इसकी वास्तविकता सामने आनी चाहिए और सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

बड़ा सवाल- क्या देवगुड़ी निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच होगी? क्या स्वीकृत राशि और मौके पर हुए निर्माण का मिलान कराया जाएगा? ग्रामीणों को अब जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।

पंजीकृत श्रमिकों के आधार डाटा संशोधन एवं ई-केवाईसी के लिए विशेष अभियान

सीएससी संचालकों एवं वीएलई को दिया गया तकनीकी प्रशिक्षण, 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही



छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित विशेष अभियान के तहत पंजीकृत श्रमिकों के आधार कार्ड के अनुरूप डाटा संशोधन एवं ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों एवं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई) का प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के आधार आधारित डाटा संशोधन एवं ई-केवाईसी की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

सभी सीएससी संचालकों एवं वीएलई को व्यक्तिगत रुचि लेकर अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य के लिए सरपंच, पंचायत सचिव एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का सहयोग लेने तथा मुनादी के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक करने कहा गया। साथ ही क्लस्टरवार कार्ययोजना बनाकर पात्र पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में श्रम पदाधिकारी श्री बी.एल. ठाकुर, ई-जिला प्रबंधक, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित सीएससी संचालक एवं वीएलई उपस्थित थे।

कोटाडोल में वन विभाग की मनमानी: बिना आदेश व दस्तावेजों के किसान को पट्टे की भूमि पर खेती करने से रोका, कस्टडी में लेने की दी धमकी

संवाददाता ➤ रायपुर



जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोटाडोल के बीचगांव में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए एक किसान को उसकी वैध पट्टे व कब्जे वाली राजस्व भूमि पर कृषि कार्य करने से रोकने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता परमानंद ने मामले का खुलासा करते हुए वन अमले पर खुलेआम तानाशाही और अवैध दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

?प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 11 अक्टूबर 2026 की दोपहर लगभग 11 बजे की है। कोटाडोल परिक्षेत्र के रेंजर ज्योति राव आदित्य, डिप्टी रेंजर रविशंकर जलधारे, बीट गार्ड भारत सिंह एवं सोनू सिंह बिना आधिकारिक वर्दी और बिना किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश अथवा वैधानिक दस्तावेजों के डायल 112 पुलिस वाहन व स्टाफ को लेकर बीचगांव स्थित किसान के खेत पर पहुंचे। अधिवक्ता परमानंद के अनुसार, संबंधित किसान के पास उक्त भूमि का वर्ष 1936 से लेकर वर्तमान तक का वैध भू-स्वामी पट्टा, राजस्व अभिलेख व निरंतर कब्जा मौजूद है। इसके बावजूद वन अधिकारियों को संबंधित खसरा नंबर तक की जानकारी नहीं थी। अधिकारियों ने किसान के वैध दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए उन्हें फर्जी करार दिया और खेत में काम तत्काल बंद करने का दबाव बनाया।

इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी

अभद्र व्यवहार एवं अनुशासनहीनता के मामले में व्याख्याता श्रीमती सविता चंद्रा निलंबित

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा की व्याख्याता श्रीमती सविता चंद्रा को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने संबंधी शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती चंद्रा के विरुद्ध विकासखंड मरवाही के ग्राम मरवाही में शासकीय कार्य के दौरान विवाद करने, उच्चाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा अनुशासनहीनता बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

प्रतिवेदन में उल्लेख है कि 9 अक्टूबर 2026 को तहसीलदार मरवाही द्वारा ग्राम मरवाही के पटवारी हल्का नंबर 4, खसरा नंबर 368/1 एवं 369/1 में दुर्गा पंडाल के सामने स्थित भूमि पर अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान श्रीमती चंद्रा द्वारा मौके पर उपस्थित होकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही, तहसीलदार एवं अतिक्रमण हटाने में संलग्न अन्य शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और उपस्थित जनसमूह को उकसाकर जनाक्रोश बढ़ाने का आरोप लगाया गया।



लोक शिक्षण संचालनालय ने उक्त कृत्य को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत श्रीमती सविता चंद्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की ओर बढ़ता मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला

मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से लेकर आधुनिक अस्पतालों तक, स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार से बदल रही जिले की तस्वीर

संवाददाता ➤ एमसीबी

किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का वास्तविक आधार वहां के नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी सोच को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है। कभी बेहतर उपचार और आधुनिक जांच सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहने वाले इस क्षेत्र में अब मेडिकल कॉलेज, आधुनिक अस्पताल, डायलिसिस केंद्र, सीटी स्कैन, अटल आरोग्य लैब तथा नवीन स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष प्रयासों और राज्य शासन की प्रतिबद्धता से जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल हुई हैं। इन प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास केवल जिला मुख्यालय या शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि खड़गवां, जनकपुर, जरौंधा और कोरिया कॉलरी जैसे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संचालित स्वास्थ्य संस्थानों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और प्रस्तावित योजनाओं का यह समन्वय आने वाले समय में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।

मेडिकल कॉलेज की शुरुआतरू चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि

मनेन्द्रगढ़ में 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का प्रवेश सत्र प्रारंभ होना जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय का आरंभ है। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने की संभावनाएं भी विकसित होंगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिकल कॉलेज से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सेवाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मनेन्द्रगढ़ में इसकी शुरुआत से जिले को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।



220 बिस्तरीय अस्पताल से उपचार क्षमता को मिल रहा विस्तार

मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तरीय अस्पताल का अस्थायी संचालन प्रारंभ होना स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर अस्पताल सेवाओं को मजबूत करने तथा अधिक मरीजों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आधार तैयार हुआ है। अस्पताल सेवाओं की क्षमता में वृद्धि का सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिन्हें पहले सामान्य से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता था। इसी प्रकार चिरमिरी में जिला अस्पताल का अस्थायी संचालन प्रारंभ किया गया है, जबकि जिला अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन भवन के पूर्ण होने से चिकित्सा सेवाओं को अधिक व्यवस्थित स्वरूप मिलने की संभावना है। अस्पताल में बेहतर अधोसंरचना विकसित होने से मरीजों को उपचार, जांच एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास भी प्राथमिकता



किसी भी अस्पताल की सफलता केवल आधुनिक भवन और उपकरणों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वहां कार्यरत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिरमिरी में डॉक्टर कॉलोनी तथा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। इन निर्माणाधीन सुविधाओं के पूर्ण होने से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सकीय अमले के लिए आवास की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर एवं प्रभावी संचालन में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के साथ मानव संसाधन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा से जांच के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता होगी कम

चिरमिरी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कक्ष एवं मशीन का संचालन प्रारंभ होना जिले के नागरिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक सीटी स्कैन सुविधा ने स्थानीय स्तर पर उन्नत चिकित्सकीय जांच का नया विकल्प उपलब्ध कराया है।

दुर्घटनाओं, सिर की चोट, आंतरिक बीमारियों एवं अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याओं में सीटी स्कैन जांच का विशेष महत्व होता है। पहले ऐसी जांच के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय के साथ आर्थिक व्यय भी बढ़ता था। स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को समय पर जांच कराने में सहायता मिलेगी और चिकित्सकों के लिए उपचार संबंधी निर्णय लेना अधिक सुविधाजनक होगा।

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई ग्राम रांपा के रामचंद्र यादव की कहानी

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से रामचंद्र यादव के परिवार को मिला खाद्य सुरक्षा का संबल

प्रतिमाह 35 किलो चावल सहित चना, शक्कर और नमक मिलने से घरेलू खर्च में राहत, परिवार की जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

संवाददाता ➤ एमसीबी

शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाला नियमित राशन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रहा है। इसी योजना से लाभान्वित जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ग्राम रापां निवासी रामचंद्र यादव के परिवार को भी बड़ी राहत मिल रही है।

रामचंद्र यादव को राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल, लगभग 2 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम शक्कर तथा 2 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है। नियमित रूप से



मिलने वाली इस राशन सामग्री से परिवार की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता मिल रही है। साथ ही बाजार से खाद्यान्न खरीदने पर होने वाले खर्च में कमी आने से परिवार के अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी आर्थिक राहत मिल रही है।

नियमित राशन से परिवार की जरूरतें हो रहीं पूरी

रामचंद्र यादव बताते हैं कि पहले परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। अब शासन की योजना के तहत नियमित राशन मिलने से परिवार को काफी सहारा मिला है। चावल के साथ चना, शक्कर और नमक जैसी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने से घर की रसोई की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। इससे परिवार को आर्थिक बचत के साथ खाद्य सुरक्षा का भरोसा भी मिला है।

जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बनी योजना

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को निर्धारित पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक राशन सामग्री पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल रही है।

न्यूज इन शॉर्ट

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संवेदनशील राहत व्यवस्था, दुर्घटना प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल

जशपुर जिले में 16 मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रत्येक प्रभावित परिवार को मिलेगी 4 लाख रुपये की सहायता, कठिन समय में परिजनों को राहत देने की पहल

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और उन्हें आर्थिक संबल देने की इसी पहल के तहत जशपुर जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 16 व्यक्तियों के निकटतम वारिसों के लिए कुल 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप समय पर सहायता मिल सके। किसी परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न दुख और क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जीवन को पुनः व्यवस्थित करने में सहायक होती है। कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत 16 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इन प्रकरणों में कुएं, तालाब, नदी, बांध एवं अन्य जलस्रोतों में डूबने से हुई मृत्यु के मामले शामिल हैं। शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत पात्र निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के विभिन्न विकासखंडों के 16 प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता जारी आदेश के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम बेमताटोली में मनीषा बाई की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ललकू राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जशपुर तहसील के ग्राम बाहमनपुर में बीकांत तिर्की की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री बरनाबास तिर्की के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। फरसाबहार तहसील के ग्राम सिंगिबहार में सरस्वती बाई की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री अनूप राम के आवेदन पर भी 4 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

मनोरा तहसील के ग्राम पटिया (अंगराकटोना) में लच्छू राम की बांध के पानी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री मधुरा राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा ग्राम रेमने में बलदेव राम की ईब नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती जगमाईत बाई के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार तपकरा तहसील के ग्राम साजबहार (कंडरापानी) में शबनम तिग्गा की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री संतोष तिग्गा के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा मनोरा तहसील के ग्राम लिटिम में मोनिका एक्का की कुएं में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ओंकार एक्का के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।फरसाबहार तहसील के ग्राम कोनपारा में नरेन्द्र डनसेना की डेम के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री राम प्रसाद डनसेना के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पत्थलगांव तहसील के ग्राम गोडीकला में विनोद महंत की कुएं में डूबने से मृत्यु के मामले में श्रीमती देवकुंवर के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा फरसाबहार तहसील के ग्राम गारीघाट (किनकेला टोला) में सागरमती बाई की कुएं में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री जयपाल साय के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है। इसी प्रकार मनोरा तहसील के ग्राम डड़गांव में सफदर अंसारी की लावा नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्रीमती चमन खातून के आवेदन पर 4 लाख रुपये, ग्राम गुल्लू में मनोज खलखो की नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती अनिता खलखो के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा फरसाबहार तहसील के ग्राम भालूमुंडा में शिवानी शाह की नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री शीतल शाह के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

युवा कार्टूनिस्ट अपनी रचनात्मकता को दें नई उड़ान, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें छत्तीसगढ़ का नाम: मुख्यमंत्री

कार्टून समाज को जागरूक करने के साथ सोचने और आत्ममंथन के लिए करता है प्रेरित : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



कार्टून केवल हास्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का सशक्त दर्पण है। यह गंभीर विषयों, सामाजिक परिस्थितियों और विसंगतियों को हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से सहजता से जनमानस तक पहुंचाने वाली प्रभावशाली रचनात्मक विधा है। कई बार जो बात हजारों शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक प्रभावशाली कार्टून बड़ी सरलता और गहराई के साथ अभिव्यक्त कर देता है। कार्टून समाज को हंसाने के साथ सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कला और साहित्य किसी भी समाज की चेतना के वाहक होते हैं। कार्टून इस दृष्टि से विशिष्ट कला है, जिसमें चित्र, विचार, हास्य और व्यंग्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक कार्टूनिस्ट अपने सूक्ष्म अवलोकन और रचनात्मक दृष्टि से सामाजिक घटनाओं को ऐसा स्वरूप देता है, जो लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्टून जनभावनाओं, जनअपेक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्ति देने का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय कार्टून कला की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर.के. लक्ष्मण का प्रसिद्ध 'कॉमन मैन' केवल एक कार्टून चरित्र नहीं, बल्कि देश के सामान्य नागरिक की आशाओं, अपेक्षाओं, जिज्ञासाओं और चिंताओं की पहचान बन गया। स्वतंत्रता के बाद बदलते भारत और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया, वह भारतीय पत्रकारिता और कार्टून कला की अमूल्य विरासत है।

ग्राम रापां के अशोक कुमार के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना बनी अशोक कुमार के परिवार की खाद्य सुरक्षा का मजबूत आधार

नियमित राशन से पांच सदस्यीय परिवार को मिल रही आर्थिक राहत, घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सहायक बनी शासन की योजना

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी



छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को नियमित रूप से आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी योजना का लाभ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ग्राम रापां निवासी अशोक कुमार के पांच सदस्यीय परिवार को भी मिल रहा है। शासन की ओर से मिलने वाली राशन सामग्री उनके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ घरेलू खर्च में राहत प्रदान कर रही है। अशोक कुमार को राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल, लगभग 2 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम शक्कर तथा 2 किलोग्राम नमक प्राप्त हो रहा है। नियमित रूप से उपलब्ध होने वाली इस खाद्य सामग्री से परिवार की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। साथ ही बाजार से राशन खरीदने पर होने वाले खर्च में कमी आने से परिवार के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भी आर्थिक सहारा मिल रहा है।

नियमित खाद्यान्न से परिवार को मिल रही राहत

अशोक कुमार बताते हैं कि पांच सदस्यीय परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण सहारा बनी है। चावल के साथ चना, शक्कर और नमक जैसी आवश्यक सामग्री नियमित रूप से मिलने से घरेलू बजट को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने से परिवार को भोजन संबंधी आवश्यकताओं की चिंता से राहत मिली है।उन्होंने बताया कि शासन की इस सुविधा से उनके परिवार को आर्थिक बचत के साथ खाद्य सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। नियमित राशन मिलने से वे अपने परिवार के साथ संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मजबूत हो रही खाद्य सुरक्षा

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को निर्धारित पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल प्रदान करने का प्रावधान है, जबकि प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस व्यवस्था से पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने के साथ घरेलू खर्च का बोझ कम करने में भी सहायता मिलती है।

सेवा संकल्प अभियान से सामने आ रही जनकल्याण की कहानियां

जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने तथा लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभवों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जनसेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत-2047 के संकल्प को मजबूत करना है। ग्राम रांपा के अशोक कुमार की कहानी इस बात का उदाहरण है कि शासन की खाद्यान्न सहायता योजना किस प्रकार जरूरतमंद परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बन रही है।

लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण: संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा

राजस्व अधिकारी प्रतिदिन दो से चार घंटे प्रकरणों के अध्ययन और निर्णय के लिए दें, आमजन को समय पर उपलब्ध कराएं नकल, नक्शा और खसरा

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी



सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों, नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, डायवर्सन, भूमि अभिलेख सुधार, नक्शा अद्यतन, न्यायालयीन मामलों सहित शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, उपायुक्त श्री आर.के. खूंटे, उपायुक्त श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश

संभागायुक्त ने 1 अक्टूबर 2025 से अब तक राजस्व न्यायालयों में दर्ज एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण के 330, अविवादित खाता विभाजन के 55 तथा विवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन के 15 लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार, नजूल तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित 46 प्रकरणों को भी शीघ्र निराकरण करने को कहा। भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार एवं प्रविष्टि संबंधी विवादों की समीक्षा के दौरान कुल 429 प्रकरणों में से 359 निराकरण तथा 70 लंबित पाए गए। इनमें 55 प्रकरण समय-सीमा से बाहर थे, जबकि 27 प्रकरणों में विलंब का कारण दर्ज नहीं था। संभागायुक्त ने ऐसे मामलों में विलंब के कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त डायवर्जन के 18 लंबित प्रकरणों तथा मनेन्द्रगढ़ में वृक्ष कटाई से संबंधित एक लंबित प्रकरण का समयबद्ध निराकरण करने को कहा। उन्होंने नक्शा अद्यतन के लिए शेष 14,320 खसरों का कार्य लक्ष्य निर्धारित कर पूरा करने तथा जिन खसरों के नक्शे उपलब्ध नहीं हैं, उनकी जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। खड़गवां और भरतपुर में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र से संबंधित कार्यों में भी प्रगति लाने पर जोर दिया।

राजस्व विभाग शासन की रीढ़, जवाबदेही से करें कार्य

संभागायुक्त श्री दुग्गा ने कहा कि राजस्व विभाग शासन की रीढ़ है और आम नागरिकों का इससे सीधा जुड़ाव होता है। इसलिए राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

रायपुर रेल मंडल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति 11 से 15 अक्टूबर तक विशेष जागरूकता अभियान

रायपुर, दुर्ग स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर स्वच्छता कर्मियों, यात्रियों को चार प्रकार के कचरे के कलर कोड डस्टबिन में पृथक्करण की जानकारी दी गई

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में 1 से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इस पखवाड़े की कड़ी में स्वच्छता को बढ़ावा देने, कार्यालयीन एवं रेलवे परिसरों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 11 से 15 अक्टूबर 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत रायपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों, डिपो, शेड एवं कार्यालयों में रेलकर्मियों तथा संविदा कर्मचारियों को चार प्रकार के कचरे के पृथक्करण के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। संबंधित डिपो, शेड एवं कार्यालयों के यूनिट प्रभारियों द्वारा अपने-अपने कार्यस्थलों पर जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कचरे को चार श्रेणियों– गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट एवं विशेष देखभाल वाले कचरे–में अलग-अलग करने पर जोर दिया जा रहा है।

अभियान के दौरान पेंट्रीकार कर्मियों और स्वच्छता प्रहरियों को को गीले कचरे, सूखे कचरे, सैनिटरी अपशिष्ट तथा विशेष देखभाल वाले अपशिष्ट को अलग-अलग एकत्र करने, निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उनका निस्तारण करने तथा कार्यस्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के महत्व की जानकारी सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश कुमार साह द्वारा दी गई साथ ही यात्रियों को भी अपने कचरे को पृथक्करण अलग-अलग डस्टबिन में डालने हेतु प्रेरित किया गया।साथ ही, कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका एवं यात्री जागरूकता पर भी जोर दिया। स्टेशनों, ट्रेनों, पेंट्री एवं रेलवे कॉलोनियों में रंग-कोडित चार-स्ट्रीम डस्टबिन की उपलब्धता एवं उपयोग की जांच तथा ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ स्टेशन सफाई कर्मियों को कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण के लिए प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है।

नई शुरुआत

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई ग्राम रापां की प्रियंका सिंह की खुशहाली की कहानी

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से प्रियंका सिंह के परिवार को मिला खाद्य सुरक्षा का भरोसा

प्रतिमाह 35 किलो चावल सहित चना, शक्कर और नमक मिलने से घरेलू खर्च में राहत, पांच सदस्यीय परिवार की जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी



शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उन्हें खाद्य सुरक्षा और आर्थिक राहत प्रदान कर रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाला नियमित राशन गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रहा है। इसी योजना से लाभान्वित जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ग्राम रापां निवासी प्रियंका सिंह के पांच सदस्यीय परिवार को भी खाद्य सुरक्षा का संबल मिल रहा है। नियमित राशन सामग्री मिलने से परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी हो रही हैं और घरेलू खर्च का बोझ कम करने में सहायता मिल रही है। प्रियंका सिंह को राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल, लगभग 2 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम शक्कर तथा 2 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है। शासन की ओर से मिलने वाली इस खाद्य सामग्री से उनके पांच सदस्यीय परिवार की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। नियमित खाद्यान्न उपलब्ध होने से परिवार को बाजार से राशन खरीदने पर होने वाले खर्च में राहत मिल रही है, जिससे अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए भी आर्थिक सहारा मिलता है।

नियमित राशन से आसान हुई परिवार की जिम्मेदारियां

प्रियंका सिंह बताती हैं कि पांच सदस्यीय परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में शासन की खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चावल के साथ चना, शक्कर और नमक जैसी आवश्यक सामग्री नियमित रूप से मिलने से घर की रसोई की जरूरतें पूरी करने में सुविधा होती है। इससे परिवार के घरेलू बजट को व्यवस्थित करने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने बताया कि शासन की इस सुविधा से परिवार को खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर राहत मिली है। नियमित राशन मिलने से वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।

जरूरतमंद परिवारों के लिए मजबूत सहारा बनी योजना

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को उनकी निर्धारित पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम चावल प्रदान करने का प्रावधान है, जबकि प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। नियमित रूप से खाद्यान्न मिलने से परिवारों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होने के साथ घरेलू खर्च में भी बचत होती है।

न्यूज इन शॉर्ट

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से भैयाथान में 5.50 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली स्वीकृति

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल और प्रयासों से सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड में सड़क निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत हुआ है। राज्य शासन ने तेलगांव मुख्य मार्ग से बरपारा होते हुए बुंदिया चौक तक 5.50 किलोमीटर लंबाई की सड़क के निर्माण के लिए 543.67 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि लगभग 5 करोड़ 43 लाख 67 हजार रूपये है।यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है। लोक निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार निर्माण के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय सहमति के बाद स्वीकृति जारी की गई है। कार्य को तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी निविदा प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ के माध्यम से कराई जाएगी।स्वीकृति आदेश में निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया गया है। स्वीकृत राशि की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित करने तथा कार्य के प्राक्कलन और निष्पादन में मितव्ययिता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्माण कार्य में किसी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।मंत्री श्रीमती राजवाड़े के प्रयासों से स्वीकृत इस सड़क से तेलगांव मुख्य मार्ग, बरपारा और बुंदिया चौक के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। सड़क बनने से स्थानीय ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में सहूलियत मिलेगी और क्षेत्र के लोगों की आवाजाही अधिक सुगम हो सकेगी।

विकास अनुज्ञा निरस्त होने पर की बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर की सौराष्ट्र रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों का पालन और घर एवं भूखंड खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले में स्थित रियल एस्टेट परियोजना सौराष्ट्र की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन भी निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की गई है।प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर श्री नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही सौराष्ट्र परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में स्थित है।
परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति निरस्त किए जाने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रकरण की समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के कारण परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने सौराष्ट्र परियोजना का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। कार्रवाई स्पष्ट करती है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन में वैधानिक अनुमतियों और निर्धारित नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उनकी विकास अनुमतियों की वैधता भी महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों एवं संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने अथवा भूखंड, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले संबंधित परियोजना के रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत विकास अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें।प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं के संबंध में भी उनकी वर्तमान पंजीयन स्थिति का सत्यापन करना आवश्यक है, ताकि नागरिक किसी प्रकार की अनियमितता या संभावित आर्थिक जोखिम से बच सकें।

कभी बैनर की दीवारों के बीच गुजरती थी जिंदगी, आज पक्के आशियाने में संवर रहे आशा के सपने

प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला अपना घर, सड़क किनारे अस्थायी आशियाने में रहने की मजबूरी हुई दूर

सेवा संकल्प अभियान 2026 - सेवा की कहानी - कभी बैनर की दीवारों के बीच गुजरती थी जिंदगी, आज पक्के आशियाने में संवर रहे आशा के सपने

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा आवास योजनाओं का लाभ

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में आवासीय सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर

सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के लिए कर रही हैं बचत, सुरक्षित भविष्य की दिशा में बढ़ाए कदम

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर



कभी सड़क किनारे बैनर से बनी दीवारें ही उनके घर का सहारा थीं। न पक्की छत थी और न ही सुरक्षित आशियाना। हर दिन परिवार की जरूरतों को पूरा करने की चिंता और बेहतर भविष्य की उम्मीद के बीच जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नवा रायपुर के सेक्टर-7 स्थित ग्राम चीचा की आशा के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना नई खुशियां लेकर आई है। कभी बैनर की दीवारों के बीच रहने वाली आशा आज अपने पक्के घर में परिवार के साथ रह रही हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि वर्षों की परेशानियों से मिली राहत, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का नया आधार है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिकों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से आशा जैसे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार मिल रहा है।

बैनर की दीवारों से पक्के घर तक का सफर

आशा के लिए अपना पक्का घर होना कभी एक बड़ा सपना था। सीमित संसाधनों के कारण उन्हें सड़क किनारे बैनर की दीवारों से बने अस्थायी घर में रहना पड़ता था। ऐसे घर में परिवार के साथ जीवन गुजारना आसान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने के बाद उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब उनके पास अपना पक्का आशियाना है, जहां वे परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रही हैं।

आशा के लिए घर मिलने की खुशी इसलिए भी खास है, क्योंकि यह उनके परिवार के भविष्य को लेकर एक नई शुरुआत है। जिस परिवार के पास कभी रहने के लिए स्थायी ठिकाना नहीं था, आज उसके पास अपना घर है। आशा इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

अब बेटियों के भविष्य को संवारने में जुटीं आशा

अपना घर मिलने के बाद आशा अब अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। एक मां के रूप में उनकी इच्छा है कि उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और भविष्य में आत्मनिर्भर बनें। इसी सोच के साथ उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी बेटियों के लिए बचत शुरू की है। वे अपनी बच्चियों के खातों में ढाई-ढाई सौ रुपये जमा कर रही हैं।

आशा के लिए यह बचत भले ही छोटी राशि से शुरू हुई हो, लेकिन इसके पीछे एक मां के बड़े सपने जुड़े हैं। वे चाहती हैं कि आने वाले समय में बेटियों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए उनके पास आर्थिक सहारा हो। नियमित बचत के माध्यम से वे आज ही अपनी बेटियों के बेहतर कल की नींव रख रही हैं।

एक योजना से मिला आशियाना, दूसरी से बेटियों के भविष्य को सहारा

आशा की कहानी जनकल्याणकारी योजनाओं से आम परिवारों के जीवन में आ रहे बदलाव का प्रेरक उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया है, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से वे बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक बचत कर रही हैं। इन दोनों योजनाओं ने उनके जीवन की दो महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को नई दिशा दी है। पहली, परिवार के लिए सुरक्षित घर और दूसरी, बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक तैयारी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और उन्हें बेहतर जीवन के अवसर मिलें। वहीं वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विजन के अनुरूप आवासीय विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई बदलाव की प्रेरक कहानी

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आशा की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब उनका लाभ जरूरतमंद परिवारों के जीवन में ठोस बदलाव लेकर आता है। कभी बैनर की दीवारों के सहारे जीवन गुजारने वाली आशा आज अपने पक्के घर में रह रही हैं और अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं।आशा की जिंदगी में आया यह बदलाव केवल एक परिवार को आवास मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक मां के संघर्ष, उम्मीद और सपनों के साकार होने की कहानी है। कभी उनकी सबसे बड़ी चिंता परिवार के लिए सुरक्षित छत थी, आज वे उस चिंता से आगे बढ़कर बेटियों के भविष्य को संवारने में जुटी हैं।

बैनर की अस्थायी दीवारों से शुरू हुआ आशा का सफर आज पक्के घर की मजबूत दीवारों तक पहुंच चुका है। अब इसी घर में उनकी बेटियों के सुनहरे भविष्य के सपने भी आकार ले रहे हैं। आशा की यह कहानी बताती है कि जब जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलता है, तो केवल उनकी वर्तमान परिस्थितियां ही नहीं बदलतीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की उम्मीदें भी मजबूत होती हैं।

जीपीएम जिले में 21 अक्टूबर से वित्तीय समावेशन का महाअभियान,

31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित होंगे वित्तीय

गांव-गांव लगेंगे शिविर, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक व्यापक वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार इस अवधि में जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष वित्तीय समावेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में कम से कम एक शिविर आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक भी बैंकिंग एवं वित्तीय सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को मिलेगी प्राथमिकता

जिला अग्रणी बैंक कार्यालय पेंड्रारोड द्वारा जारी पत्र के अनुसार वित्तीय समावेशन अभियान का प्रमुख उद्देश्य ऐसे नागरिकों और परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, जिनकी अब तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं हो सकी है। शिविरों में पात्र नागरिकों के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से नागरिकों को बचत, बैंकिंग लेनदेन और विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुविधाओं से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

अभियान के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे परिवारों के जनधन खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना से मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का संबल

वित्तीय समावेशन शिविरों में पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों को वार्षिक 436 रुपये प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर उपलब्ध होता है। यह योजना बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

बिहान से बदल रही ग्रामीण महिलाओं की तकदीर

आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहीं जीपीएम की 59 हजार से अधिक महिलाएं



महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती, स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रहे महिलाओं के कदम

बचत, बैंकिंग, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों से महिलाओं के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर उभर रही है। कभी घर-परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली ग्रामीण महिलाएं अब संगठित होकर आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित श्बिहानश् योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रही है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हजारों महिलाएं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संगठित होकर बचत, वित्तीय प्रबंधन, स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा रही हैं। बिहान मिशन महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।

5,576 स्व-सहायता समूहों में संगठित हुईं 59,524 महिलाएं

जिले में बिहान मिशन के अंतर्गत महिलाओं को संगठित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन की 13 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति के अनुसार जिले में कुल 5,576 स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनसे 59,524 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं में सामूहिक संगठन, आर्थिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार गौरेला विकासखंड में 1,828 स्व-सहायता समूहों से 19,654 महिलाएं जुड़ी हैं। इसी प्रकार पेंड्रा विकासखंड में 1,603 समूहों के माध्यम से 17,612 महिलाएं तथा मरवाही विकासखंड में 2,145 समूहों से 22,258 महिलाएं संगठित हुई हैं। जिले में समूहों की संख्या और महिलाओं की भागीदारी के मामले में मरवाही विकासखंड अग्रणी है। इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को एक साझा मंच मिल रहा है, जहां वे अपनी आर्थिक जरूरतों, बचत, आजीविका और सामूहिक विकास से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने में भागीदारी कर रही हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में 676 नए समूहों का गठन, 12 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ीं

महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिले में बिहान मिशन का विस्तार निरंतर जारी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 676 नए स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनसे 12,029 महिलाएं जुड़ी हैं। नए समूहों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें संगठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।चालू वित्तीय वर्ष में गौरेला विकासखंड में 211 नए स्व-सहायता समूहों का गठन कर 4,189 महिलाओं को जोड़ा गया है। पेंड्रा विकासखंड में 130 नए समूहों से 3,302 महिलाएं तथा मरवाही विकासखंड में 335 नए समूहों से 4,538 महिलाएं जुड़ी हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिले के तीनों विकासखंडों में महिलाओं को सामूहिक संगठन से जोड़ने के प्रयासों को गति मिली है। विशेष रूप से मरवाही विकासखंड में नए समूहों का गठन महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

बचत और बैंकिंग से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

बिहान मिशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना है। स्व-सहायता समूह महिलाओं में नियमित बचत की आदत विकसित करने, सामूहिक वित्तीय निर्णय लेने और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। समूहों के माध्यम से महिलाएं अपनी छोटी-छोटी बचत को संगठित कर आर्थिक जरूरतों की पूर्ति और भविष्य की योजनाओं के लिए वित्तीय आधार तैयार कर सकती हैं।मिशन के अंतर्गत महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, ऋण सुविधाओं और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाता है।

आंगनबाड़ियों के माध्यम में वितरित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिलेट फसलों के उपार्जन, उत्पादन एवं उपयोग के संबंध में बैठक सम्पन्न

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कोदो, कुटकी, रागी तथा मक्का के उपार्जन एवं फसल विविधीकरण, किसानों को प्रोत्साहित करने सहित अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा हुई।



बैठक में इन कृषि उत्पादों की आवश्यकता, उपार्जन तथा मिलेटस के उपयोग के संबंध में चर्चा हुई। इसके तहत स्कूलों में मध्यांह भोजन और महिला एवं बाल विकास के पोषक आहार कार्यक्रमों में आंगनबाड़ियों के माध्यम में वितरित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

भुवनेश्वर के बाद अब शमी की होगी टीम में एंट्री?



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी के बाद अब सीनियर पेसर मोहम्मद शमी को लेकर भी चर्चाओं का माहौल गर्म है। शमी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमबैक को लेकर दिग्गज लगातार अपनी राय दे रहे हैं। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने मोहम्मद शमी को टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में तुरंत वापस लाने की जोरदार वकालत की है। एमएसके प्रसाद से पहले भी कई दिग्गज शमी को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भुवी की वापसी पर बात करते हुए एमएसके प्रसाद ने इंडिया टुडे से कहा कि पिछले दो-तीन आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 से अधिक विकेट लेने वाले भुवनेश्वर पूरी तरह से इस वापसी के हकदार थे।

वनडे और टेस्ट टीम में होनी चाहिए शमी की वापसी

भुवनेश्वर की सफलता के बाद पूर्व चीफ सिलेक्टर का मानना है कि चयनकर्ताओं को मोहम्मद शमी के नाम पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। शमी ने रणजी ट्रॉफी के नए सीजन की शुरुआत दिल्ली के खिलाफ चार विकेट लेकर शानदार अंदाज में की है।प्रसाद ने कहा कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो 2015, 2019 और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए दमदार प्रदर्शन कर चुका हो और अब भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा हो, मैं उसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम में खेलते हुए देखना पसंद करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर होते हैं तो भारतीय टीम को अनुभव की कमी खलती है। ऐसे में शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा ।

विलियम ने बल्ला थामकर खेल का आनंद लिया



लंदन में आयोजित 'क्रिकेट एट द मॉल' कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम क्रिकेट के मैदान पर अपने हाथ आजमाते नजर आए. अर्थशॉट प्राइज के इस खास आयोजन में ब्रिटेन और भारत के क्रिकेट सितारों के साथ शामिल हुए प्रिंस विलियम ने बल्ला थामकर खेल का आनंद लिया।

चौथे टी20 में होगा बड़ा धमाका



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास चौथे टी20 मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। इंदौर में तीन विकेट चटकाने वाले अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में गेंद से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद में वह एक बार फिर अपना दमखम दिखा सकते हैं।भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 14 अक्टूबर (बुधवार) को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास बड़ा कारनामा करने का मौका है।अर्शदीप सिंह वह कर सकते हैं जो आज तक भारत का कोई भी तेज गेंदबाज नहीं कर सका है। अर्शदीप सिंह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे करने से महज 6 विकेट दूर हैं।

भारत के लिए अब तक 97 टी20ह्ल मैच खेल चुके अर्शदीप के नाम 144 विकेट दर्ज हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 51 रन देकर 5 विकेट रहा है। टी20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड शानदार रहा है। विकेट चटका लेते हैं ।

आकृति अग्रवाल ने इसी साल मार्च में सगाई की थी।

रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के लिए रणजी ट्रॉफी 2026-27 के सीजन की शुरुआत अच्छी रही। महाराष्ट्र के कप्तान पृथ्वी ने सर्विसेज के खिलाफ 73 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली। में अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया। पृथ्वी की इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने पहली पारी में 333 रन बनाए।पृथ्वी शॉ की इस पारी के बीच उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल का सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है। आकृति ने 12 अक्टूबर को ही पृथ्वी के साथ रिश्ते दोबारा सुधारने का ऐलान किया।इससे पहले 17 सितंबर को उन्होंने सगाई तोड़ने की घोषणा की थी। करीब एक महीने के भीतर ही अब उन्होंने अपने फैसले को बदलते हुए रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने की बात कही है।मार्च में हुई थी सगाई पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने इसी साल मार्च में सगाई की थी। लेकिन 17 सितंबर को

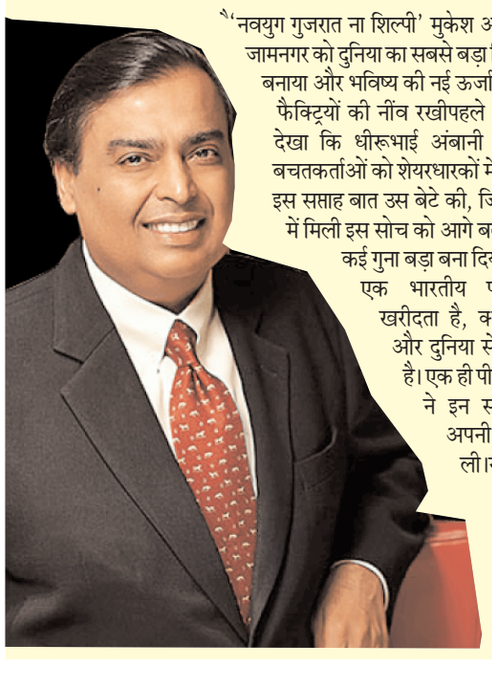


आकृति ने सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब सोमवार (12 अक्टूबर) को उनके पैचअप वाले पोस्ट ने दोनों के रिश्ते को लेकर फिर से चर्चा शुरू कर दी है।

अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट शेयर किया, जिसे पृथ्वी शॉ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लगाया था। ने लिखा- जब मैंने अपनी सगाई तोड़ी थी, तब मैंने अपने करीबी लोगों की राय को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था, जो लोग हमारी रिश्ते को हमसे बेहतर जानते लग रहे थे। उनकी बातों ने मेरे मन में अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते के बारे में गलत तस्वीर बना दी। मुझे लगता है कि मैं गुमराह हो गई थी और हम दोनों के बीच वह ईमानदार बातचीत किए बिना ही मैंने फैसला ले लिया, जिसके हम हकदार थे।उस फैसले और उससे हुए दर्द की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूं।उसके बाद हम दोनों ने खुलकर बात की, एक-दूसरे को समझा और फिर से एक साथ रहने का फैसला किया।

व्यापार

जामनगरः जहाँ गुजरात दुनिया की ऊर्जा को नया आकार देता है और भविष्य का निर्माण करता है



"नवयुग गुजरात ना शिल्पी' मुकेश अंबानी ने कैसे जामनगर को दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बनाया और भविष्य की नई ऊर्जा के लिए गीगा फैक्ट्रियों की नींव रखीपहले भाग में हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी ने भारत के बचतकर्ताओं को शेयरधारकों में कैसे बदला। इस सप्ताह बात उस बेटे की, जिसने विरासत में मिली इस सोच को आगे बढ़ाया और उसे कई गुना बड़ा बना दिया।सोचिए कि एक भारतीय परिवार क्या खरीदता है, क्या देखता है और दुनिया से कैसे जुड़ता है। एक ही पीढ़ी में रिलायंस ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली।नरोदा की कपड़ा मिल ने सबसे पहले रिलायंस को भारतीय घरों में पहचान दिलाई थी। मुकेश अंबानी ने इस जुड़ाव को कहीं आगे बढ़ाया। रिलायंस रिटेल ने बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक संगठित खरीदारी की सुविधा पहुँचाई। इसके बाद मीडिया और मनोरंजन, डिजिटल सेवाओं और अंततः दूरसंचार के क्षेत्र में भी रिलायंस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह रिलायंस परिवार के कपड़ों के लिए धागा बनाने वाली कंपनी से आगे बढ़कर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई।

विरासत से कहीं बड़ा साम्राज्य

एक महान उद्योग खड़ा करना कठिन है। लेकिन विरासत में मिले उद्योग को संभालते हुए उसे कहीं अधिक बड़ा बनाना एक अलग ही चुनौती है।2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के समय रिलायंस पहले ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहों में शामिल हो चुकी थी। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि उनके उत्तराधिकारी का काम केवल इस विरासत को सुरक्षित रखना होगा। लेकिन मुकेश अंबानी ने इससे बड़ा लक्ष्य तय किया। उन्होंने अपने पिता की दूरदर्शिता, मांग से पहले निवेश करने और पूरे उद्योग क्षेत्र की दिशा बदलने वाली सोच को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।हर नए कारोबार में उनकी रणनीति वही थी, जिसकी शुरुआत धीरूभाई ने की थी–असीम संभावनाओं वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना, बड़े पैमाने पर निवेश करना, पुरानी धारणाओं को चुनौती देना और नए बाजार तैयार करना।

जामनगर- भारत की निर्माण क्षमता का प्रतीक

सौराष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित जामनगर में यह महत्वाकांक्षा सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में जामनगर दुनिया के सबसे बड़े एकल-स्थल तेल रिफाइनिंग परिसरों में विकसित हुआ। यह ऐसा औद्योगिक केंद्र है, जहाँ भारतीय इंजीनियरिंग वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करती है और विभिन्न महाद्वीपों के बाजारों को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया जाता है।जामनगर गुजरात के लिए केवल एक औद्योगिक ठिकाना बनकर नहीं रहा। इसने निवेश, रोजगार, तकनीकी कौशल और आपूर्तिकर्ताओं व सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक तंत्र विकसित किया। साथ ही, गुजरात को दुनिया के ऊर्जा मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया।आज यही क्षेत्र धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का भी केंद्र है, जो भविष्य की ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस के बढ़ते कदमों का प्रतीक है।

निवेशकों के साथ रिश्ता आज भी कायम

इस पूरी विकास यात्रा के दौरान संस्थापक की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार रहा–आम निवेशकों के साथ जुड़ाव।2006 में रिलायंस पेट्रोलियम ने एक बड़े सार्वजनिक निर्गम के जरिए पूंजी बाजार में प्रवेश किया। इससे रिलायंस के एक और बड़े कारोबार में आम निवेशकों की भागीदारी का अवसर मिला। वर्ष 2009 में रिलायंस पेट्रोलियम का रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय हो गया।

1977 से रिलायंस की यात्रा पर नजर रखने वाले परिवारों के लिए यह दशकों से चले आ रहे रिश्ते का एक और अध्याय था।पिता ने भारत के मध्यम वर्ग को यह विश्वास दिलाया कि वह औद्योगिक विकास में हिस्सेदार बन सकता है। बेटे ने दिखाया कि यही विकास वैश्विक स्तर पर कितना व्यापक रूप ले सकता है। इसी कारण मुकेश अंबानी को 'नवयुग गुजरात ना शिल्पी', यानी नए युग के गुजरात का शिल्पकार, कहना उचित है।लेकिन इस कहानी का सबसे नाटकीय अध्याय अभी बाकी था। और इसकी शुरुआत किसी बोर्डरूम में नहीं, बल्कि परिवार की अपनी भोजन की मेज पर होने वाली बातचीत से होने वाली थी।

पीढ़ियों के बीच साझेदारी

जामनगर की उपलब्धि केवल एक परिवार की उपलब्धि नहीं है। यह गुजरात की धरती और उसके समुद्र तट पर खड़ा हुआ ऐसा औद्योगिक केंद्र है, जिसे यहाँ के श्रमिकों ने बनाया और स्थानीय समुदायों के विश्वास ने मजबूती दी। आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से लेकर निवेशकों तक, इस विकास यात्रा में अनेक लोगों की भागीदारी रही है।1977 के शेयरधारकों से लेकर आज रिलायंस की वैश्विक पहुँच को शक्ति देने वाले समुदायों तक, यह साझेदारी हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ी है। गुजरात ने इस कहानी को कभी केवल दर्शक बनकर नहीं देखा, बल्कि इसे आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जब यह यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, तब भी इस कहानी को लिखने वाले राज्य के पास इसमें अपनी जगह है।इस श्रृंखला का अगला भाग- बेटी की शिकायत, बेटे की दूरदृष्टि और परिवार के बीच वह बातचीत, जिसने भारत को जोड़ा।

बोनस शेयर का प्लान टला; पहली तिमाही में मुनाफा 79त्न बढ़कर ?220 करोड़ रहा

रिजल्ट के बाद पेटीएम का शेयर 4प्रतिशत फिसला

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद पेटीएम के शेयरों में आज मंगलवार 21 जुलाई को गिरावट रही। बाजार खुलते ही शेयर में 2.5त्न से ज्यादा की तेजी आई, लेकिन थोड़ी ही देर में यह गिर गया। ये 3.86त्न नीचे ?1295 पर बंद हुआ।

विजय शेखर शर्मा की अगुआई वाली इस फिनटेक कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा है। पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 79त्न बढ़कर 220 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। लेकिन बोनस शेयर टलने की खबर से बिकवाली का दबाव बढ़ा है।

पेटीएम ने 2 सालों में निवेशकों का पैसा लगभग तीन गुना किया

कंपनी के शेयर ने बीते 2 सालों में निवेशकों का पैसा लगभग तीन गुना किया है। हालांकि, मार्केट डेब्यू के करीब 5 साल बाद भी यह शेयर अपने आईपीओ प्राइस ?2,150 से नीचे है। 30 जून 2026 को समाप्त हुई इस तिमाही में ऑपरेशन्स से पेटीएम का रेवेन्यू 28त्न बढ़कर ?2,448 करोड़ पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में ?1,918 करोड़ था। वहीं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 79त्न बढ़कर ?220 करोड़ रहा है।

कंपनी को अपने पेमेंट बिजनेस, मर्चेंट सब्सक्रिप्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन में लगातार ग्रोथ से यह मुनाफा हासिल हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में पेटीएम को ?123 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं, मार्च तिमाही में ?183 करोड़ का मुनाफा हुआ था।

पेटीएम मनी में ?100 करोड़ के निवेश को मंजूरी
पेटीएम के बोर्ड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी पेटीएम मनी में राइट्स इश्यू के जरिए ?100 करोड़ तक के निवेश को मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में निवेश, रेगुलेटरी कैपिटल जरूरतों को पूरा करने और कंपनी के इन्वेस्टमेंट व वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के विस्तार के लिए किया जाएगा।

आईपीओ के बचे 1,686 करोड़ के इस्तेमाल का प्लान बदला

कंपनी के बोर्ड ने आईपीओ से मिली अनयूज्ड 1,686 करोड़ की बची हुई रकम के इस्तेमाल और उसकी समय-सीमा में बदलाव का प्रस्ताव भी पास किया है। बोर्ड ने इस रकम के उपयोग का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2029 तक करने के लिए शेयरहोल्डर्स से मंजूरी लेने का फैसला किया है।

कंपनी का कहना है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी से उसे पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रोथ के नए मौकों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

बोनस शेयर का प्लान क्यों टला?

कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव टाल दिया है। बोर्ड ने कहा कि लॉन्ग-टर्म शेयरहोल्डर वैल्यू के नजरिए से प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला लिया गया है।बोर्ड का मानना है कि कंपनी को अभी अपनी ग्रोथ बढ़ाने और प्रॉफिटेबिलिटी को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि शेयरधारकों के लिए बेहतर वैल्यू क्रिएट हो सके। के बिजनेस हेड हर्षल दसानी के मुताबिक, पेटीएम का क्त्रा स्त्रङ्ख27 रिजल्ट इस बात का साफ सबूत है कि कंपनी अब टर्नअराउंड फेज से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी फेज में आ चुकी है। 28त्न की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ ?203 करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही श्वञ्चह्लङ्घञ्ज और ?220 करोड़ का मुनाफा दिखाता है कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर अब मजबूत हो चुका है। अब बढ़ता रेवेन्यू सीधे मुनाफे में बदल रहा है।

अडाणी एनर्जी का मुनाफा 124त्न बढ़कर 1,149 करोड़:पहली तिमाही में रेवेन्यू 42त्न चढ़ा;

एजेंसी ➤ मुंबई

अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोगुना से ज्यादा यानी 124त्न बढ़कर 1,149 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

कंपनी की कुल कमाई में तेज बढ़ोतरी और रेगुलेटरी डेफरल इनकम में आए पॉजिटिव बदलाव से नतीजों को मजबूती मिली है। नतीजों की घोषणा के बाद अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर दोपहर के कारोबार में 3त्न चढ़कर 1,781.2 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि, यह 1,737 रुपए पर बंद हुआ।

कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 42त्न बढ़ा

कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 42.4त्न बढ़कर 9,711 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 6,819 करोड़ रुपए था। कंपनी का ऑपरेशनल मुनाफा (श्वञ्चह्लङ्घञ्ज) 30त्न बढ़कर 3,008 करोड़ रुपए रहा। हालांकि, श्वञ्चह्लङ्घञ्ज मार्जिन में मामूली गिरावट देखी गई और यह पिछले साल के 33.9त्न से घटकर 31त्न पर आ गया।

कंपनी को रेगुलेटरी इनकम का मिला फायदा

कंपनी ने पहली तिमाही में 29 करोड़ रुपए की रेगुलेटरी डेफरल इनकम दर्ज की है। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 504 करोड़ रुपए का रेगुलेटरी डेफरल खर्च उठाना पड़ा था। इस पॉजिटिव बदलाव ने कंपनी के नेट मुनाफे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

कंपनी के बिजनेस सेगमेंट का परफॉर्मेंस

कंपनी के अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हैज

ट्रांसमिशन बिजनेसः कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 52.4त्न की भारी बढ़ोतरी के साथ 3,335.3 करोड़ रुपए पहुंच गया।

डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसः इस सेगमेंट से रेवेन्यू 5त्न बढ़कर 3,520.4 करोड़ रुपए हो गया।

स्मार्ट मीटरिंग बिजनेसः इसमें 200त्न से अधिक की ग्रोथ दर्ज की गई और रेवेन्यू 346.9 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

एनर्जी सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्मः इस प्लेटफॉर्म से होने वाला रेवेन्यू 9 गुना से ज्यादा उछलकर 1,906.8 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।



आनंद की फिटनेस

हिमाचल में चिट्टा, अवैध शराब और खनन के समाचारों के बीच एक सुखद समाचार कांगड़ा से मिला। उपमंडल अधिकारी डा. अंजलि गर्ग ने युवा धमनियों में जोश भरते हुए बाइपास स्थित बाण गंगा घाट को जागृति का प्रतीक बना दिया। तीन दिवसीय फिटनेस महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य युवा पीढ़ी को ऐसे आनंद से जोडऩा था, जो इनके लक्ष्यों में शारीरिक शुद्धिकरण का पैगाम सहजता से भर गया। युवाओं ने इस दौरान खुशी का इजहार करके हुए योग, कसरत, नृत्य तथा मानसिक शांति के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत खुद की क्षमता और खुद को पाने की अभिलाषा के प्रति अभिप्रेत किया। ऐसे प्रयोग भले ही छोटे और अप्रचारित रह जाएं, लेकिन युवाओं में आनंद के सरोकार अगर कार्यक्रमों में पैदा हों, तो परिणामों की मंजिल पर हर घर मुस्कराएगा। आज जबकि हिमाचल चिट्टे व विभिन्न नशों की गिरफ्त में अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने में लगा है, एसडीएम महोदया ने युवा मनोरंजन का सफर बदल दिया। इसी तरह के प्रयास अगर हर शिक्षण संस्थान में लगातार किए जाएं, तो आनंद की दौलत शिक्षा के साथ-साथ मिलेगी। यह इसलिए भी क्योंकि जब फिटनेस का महोत्सव कांगड़ा में चल रहा था, तो कहीं इससे भिन्न तस्वीर में चिट्टा बिक्री के सबूत युवाओं के भ्रमित चरित्र की गवाही दे रहे थे। जिला के भवारना में अवैध शराब का माफिया अगर धर दबोचा गया, तो सामाजिक तहों में बर्बादी के लक्षण मिले। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान के तहत भवारना में 150 पेटियां अवैध शराब बरामद की गईं, जबकि इसके हाशिए के भीतर एक बॉटलिंग प्लांट के तहत चंडीगढ़ और पंजाब मार्के का शराब अवैध ढंग से तैयार हो रहा था ऐसा शायद ही कोई अवसर होगा जब घातक नशे की बिक्री के निशान न मिलते होंगे, वरना समाज के खोमचे में पतन की परछाइयां लंबी हो रही हैं। कांगड़ा महोत्सव में अगर कुछ बच्चे भी जिंदगी का अनुशासन सीख गए होंगे, तो यह आयोजन बेशकीमती व अनुकरणीय है। यूं तो हिमाचल में सांस्कृतिक महोत्सवों की कमी नहीं, लेकिन संगीत के नाम पर परोसी जा रही फूहड़ता का शायद ही कोई औचित्य बचता है। युवा पीढ़ी में अनुशासन के बीज या तो शिक्षण संस्थाओं में बोए जा सकते हैं या उनकी आशाओं और आकांक्षाओं में आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। हिमाचल में पहले ग्रामीण खेलों का वातावरण कमोबेश पंचायत स्तर पर सुनिश्चित होता था। कम से कम वॉलीबाल ग्राउंड तो हर गांव की खेल तहजीब को पुख्ता करता था। इसके अलावा ग्रामीण मेलों के आयोजन में छिंज के माध्यम से पहलवानी का गैर-पेशेवर अंदाज भी युवाओं की पैरवी करता था। विडंबना यह है कि शिक्षा ने खुद को दुकान और युवा पीढ़ी की महत्त्वाकांक्षा को बिक्री का सामान बना दिया। स्कूल से किसी अकादमी की सीढिय़ां चढ़ते-चढ़ते बच्चे अक्सर मोटे दावों के बीच खोखले हो जाते हैं। जाहिर तौर पर पाठ्यक्रमों की जद में युवावस्था का समय चकनाचूर हो रहा है। खास तौर पर निजी स्कूलों में पढ़ाई के माहौल को बेचने के सिलसिले ने जिस तरह बच्चों से सकून छीन लिया है, वहां क्षुब्ध भावनाएं गलत रास्तों में खुद को चुन लेती हैं। कम से कम स्कूली स्तर पर बच्चों के मन से शिक्षा का अप्राकृतिक बोझ हटाने के लिए उनके मानसिक व शारीरिक विकास को राहत व आनंद के पैगाम देने होंगे।

विचार

महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा बिहान

ए.बी काशी

सहायक संचालक, जनसंपर्क

सामूहिक प्रयासों से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने का आत्मविश्वास और परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ रही है। बिहान मिशन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं को सामूहिक शक्ति का एहसास कराना है। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रही है। स्व-सहायता समूहों का विस्तार इस बात का परिचायक है कि जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। जिले में बिहान मिशन के माध्यम से महिलाओं का संगठनात्मक विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महिलाओं को स्वरोजगार और आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के साथ परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। बिहान के माध्यम से महिलाओं की सामूहिक शक्ति को आर्थिक प्रगति में बदलने का यह प्रयास आत्मनिर्भर गांव, सशक्त महिला और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

/ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिले में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं संगठित होकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। बिहान से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं में बचत, सामूहिक भागीदारी, वित्तीय प्रबंधन और स्वरोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। यह मिशन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम बन रहा है। जिले में बिहान मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के गठन एवं महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मिशन की 13 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति के अनुसार जिले में कुल 5576 स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनसे 59524 महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें गौरेला विकासखंड में 1828 समूहों से 19654 महिलाएं, पेंड्रा विकासखंड में 1603 समूहों से 17612 महिलाएं तथा मरवाही विकासखंड में 2145 समूहों से 22258 महिलाएं जुड़ी हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी बिहान मिशन के अंतर्गत महिलाओं को संगठित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 676 नए स्व-सहायता समूहों का गठन कर 12029 महिलाओं को समूहों से जोड़ा गया है। इनमें गौरेला विकासखंड में 211 समूहों से 4189 महिलाएं, पेंड्रा में 130 समूहों से 3302 महिलाएं तथा मरवाही में 335 समूहों से 4538 महिलाएं जुड़ी हैं। बिहान मिशन ग्रामीण महिलाओं



को केवल समूहों से जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बचत, बैंकिंग सेवाओं, ऋण सुविधा, कौशल विकास और आजीविका के विविध अवसरों से जोड़ने का माध्यम भी है। स्व-सहायता समूहों के जरिए महिलाएं कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण एवं स्थानीय उत्पादों के निर्माण और विपणन जैसे कार्यों में आगे बढ़ सकती हैं। सामूहिक प्रयासों से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने का आत्मविश्वास और परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ रही है। बिहान मिशन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं को सामूहिक शक्ति का एहसास कराना है। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रही है। स्व-सहायता समूहों का विस्तार इस बात का परिचायक है कि जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं।

जिले में बिहान मिशन के माध्यम से महिलाओं का संगठनात्मक विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महिलाओं को स्वरोजगार और आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के साथ परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। बिहान के माध्यम से महिलाओं की सामूहिक शक्ति को आर्थिक प्रगति में बदलने का यह प्रयास आत्मनिर्भर गांव, सशक्त महिला और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

विचार

गांव में ही लिखी जा सकती है विकास की इबारत

डा. सतपाल

लेखक

हिमाचल के जिन दूरस्थ गांवों में सामान्य परिस्थितियों में बाहरी दुनिया की नजर कम पहुंचती है, वे अपने भीतर इतिहास, संस्कृति, परंपरा और पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं। ऐसे गांवों की यात्रा प्रशासनिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। हिमाचल का पर्यटन लंबे समय से शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुछ अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के आसपास केंद्रित रहा है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन को गांवों तक ले जाया जाए और गांवों को पर्यटन का लाभार्थी बनाया जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन केवल भोजन नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं।

यदि इस संवाद को स्थानीय रोजगार, पर्यटन, कृषि-बागवानी, महिला समूहों, युवाओं और ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ा जाए तो हिमाचल के गांव अपनी समस्याओं के साथ-साथ अपनी संभावनाओं के लिए भी पहचाने जाएंगे।हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 17वां राज्य है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां इसे देश के अन्य राज्यों से अलग पहचान देती हैं। यहां की 90 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराएं, खानपान, वेशभूषा, कृषि.बागवानी, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर गांवों में ही दिखाई देती है। इसलिए यदि हिमाचल के समग्र विकास की बात आएगी तो उसकी राह गांवों से होकर ही गुजरे यह ध्यान देना आवश्यक है। इसी सोच के साथ वर्ष 2024 में प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं को योजनाओं और बजट से जोडऩा है, अर्थात शासन की प्रक्रिया केवल कार्यालयों एवं फाइलों तक सीमित न रहकर गांव के लोगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़े, यही सरकार का प्रयास है। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में गांव तक पहुंचना केवल राजनीतिक या प्रशासनिक दौरा नहीं है, बल्कि गांव के परिवेश को समझने का अवसर है। सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली, पेयजल और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं की चुनौतियां दूरस्थ गांवों में आज भी अलग रूप में दिखाई देती हैं। इसलिए जब शासन का मुखिया स्वयं ऐसे क्षेत्रों में पहुंचता है तो उसके सामने उन समस्याओं की वास्तविक तस्वीर आती है जो राजधानी या जिला मुख्यालय की बैठकों में आंकड़ों के रूप में दिखाई देती हैं। डोडराक्वार, कुपवी, कुल्लू के सरची-बागा सराहन और कांगड़ा के बड़ा भंगाल जैसे क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के दौरों ने इसी पहलू को सामने रखा है।हाल में रोहडू के भटवाड़ी व रामपुर के काशापाट में भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इन दुर्गम क्षेत्रों का दौरा मात्र नहीं किया बल्कि वहां रात्रि प्रवास करने वाले हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित इन क्षेत्रों में पहुंचना अपने आप में प्रशासन के सामने मौजूद चुनौतियों को समझने का अवसर होता है तथा वहां रहने वाले ग्रामीणों से संवाद, उनकी



समस्याओं को सुनना और विकास संबंधी घोषणाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मुख्यमंत्री का गांवों में जाना केवल समस्याओं को सुनने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे गांवों की अपनी पहचान भी व्यापक स्तर पर सामने आती है। हिमाचल के जिन दूरस्थ गांवों में सामान्य परिस्थितियों में बाहरी दुनिया की नजर कम पहुंचती है, वे अपने भीतर इतिहास, संस्कृति, परंपरा और पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं। ऐसे गांवों की यात्रा प्रशासनिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। हिमाचल का पर्यटन लंबे समय से शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुछ अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के आसपास केंद्रित रहा है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन को गांवों तक ले जाया जाए और गांवों को पर्यटन का लाभार्थी बनाया जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन केवल भोजन नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। मक्की की रोटी, सिड्डू, धाम के व्यंजन, राजमाह, मदरा, सेपू बड़ी, चिलड़ा और विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय पकवान अपनी अलग पहचान रखते हैं। यदि ये पर्यटन से जुड़ते हैं तो निश्चित ही स्थानीय महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।इसी तरह पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प, लोकनृत्य और स्थानीय उत्पाद ग्रामीण पर्यटन को एक विशिष्ट पहचान दे सकते हैं। दरअसल, 'सरकार गांव के द्वार' को केवल शिकायत निवारण कार्यक्रम के रूप में देखने के बजाय इसे ग्रामीण विकास की व्यापक सोच से जोडऩे की आवश्यकता है। गांव में पहुंचने के बाद अगला सवाल यह होना चाहिए कि उस गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। कहीं बागवानी की संभावना है, कहीं प्राकृतिक खेती की, कहीं पर्यटन की, कहीं हस्तशिल्प की तो कहीं स्थानीय खाद्य उत्पादों की। सरकार यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बुनियादी ढांचे, विपणन, प्रशिक्षण, इंटरनेट और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराए तो गांव केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि स्थानीय आर्थिक विकास के केंद्र बन सकते हैं। यह बदलाव शासन की कार्यशैली के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक विकास की योजनाएं ऊपर से नीचे की ओर बनती रही हैं, राजधानी में नीति तैयार हुई, विभागों ने योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन गांव में हुआ। अब आवश्यकता नीचे से ऊपर की ओर योजना निर्माण की है, यही सरकार का ध्येय भी है। हालांकि इस पहल की वास्तविक सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि मुख्यमंत्री कितने गांवों में पहुंचे या कितने लोगों से संवाद किया। इसकी सफलता

(एक नजर)

360 दिन बैंक लॉकर में रहती हैं मां दुर्गा!

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा अपनी अनोखी परंपरा, इतिहास और स्वर्ण प्रतिमा के कारण खास पहचान रखती है। यहां मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा साल के लगभग 360 दिन बैंक लॉकर में सुरक्षित रहती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी के दिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मां की स्वर्ण प्रतिमा को बैंक लॉकर से निकालकर जयपुर राजबाड़ी लाया जाता है। इस दौरान यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद दशमी के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच स्वर्ण प्रतिमा को दोबारा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है।जयपुर राजबाड़ी की इस पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा और चांदी का चालचित्र है। मां की प्रतिमा द्विभुजा स्वरूप में है। इस अनोखी प्रतिमा को देखने के लिए पुरुलिया के अलावा दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं।ब 400 साल पुरानी परंपरा से जुड़ी है।

विचार

संदीप कुमार सिंह

लेखक

नरेंद्र मोदी की सियासत के 25 साल

यह मोदी का दुर्भाग्य रहा कि उनके गुजरात की सत्ता संभालने के महज छह महीने बाद ही राज्य को गोधरा कांड के चलते भयानक सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा। गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में 1044 लोगों के मारे गए , जबकि 2548 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 223 लोग लापता बताए गए।

सात अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कोई नहीं सोच रहा था कि मोदी एक साल का भी कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। राजनीतिक जानकारों और गुजरात के लोगों की इस सोच के पीछे कुछ खास वजहें भी थीं। मोदी के गुजरात का सरदार बनने से पहले के पांच वर्षों में राज्य में एक-एक करके चार मुख्यमंत्री आए और चले गए थे। मोदी राज्य के किसी ताकतवर जाति समुदाय से भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। हां, पर्दे के पीछे की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर वे स्थापित थे। इतना ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों के बीजेपी प्रभारी के रूप में



भी अपनी सियासी समझ का भी वे लोहा मनवा चुके थे। लेकिन वक्त के साथ, मोदी ने सभी आशंकाओं को ना सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि चौथाई सदी तक लगातार सत्ता का केंद्र बिंदु रहने वाले वाली शख्सियत भी बन चुके हैं। इसके पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु के नाम देश में सबसे लंबे समय यानी करीब 23 साल सत्ता संभालने का रिकॉर्ड था। मोदी उस रिकॉर्ड से भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। हाल के दिनों में एक वरिष्ठ हिंदी पत्रकार मोदी मार्ग की अवधारणा देकर आलोचनाओं के केंद्र में हैं। मोदी मार्ग की चर्चा हो तो वामपंथी तो सांड़ की तरह भड़केंगे ही, वे समाजवादी भी वरिष्ठ पत्रकार के आलोचक हो गए हैं, जो कभी उनके सहयोगी रहे या वे उनके साथी रहे। बेशक मोदी मार्ग की इन दिनों आलोचना हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब नरेंद्र मोदी का अपना और उनके दौर के भारत का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित तौर पर मोदी मार्ग या मोदीत्व की अवधारणा को भी स्वीकार किया जाएगा। किसी शख्सियत के जरिए शुरू पंथ या वैचारिक धारा को उसके जीवन काल में सर्व मान्यता और स्वीकार्यता कम ही मिल पाती है। लेकिन जब वही शख्सियत इतिहास की धारा में विलीन हो जाती है, तो उसकी दिखाई राहों को पंथ का दर्जा मिलने लगता है। गांधी बेशक अपनी जिंदगी में ही महात्मा के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनके कई प्रयोगों की उसी तरह आलोचनाएं होती रहीं, जैसे आज मोदी के वैचारिक विरोधी उनके तमाम कदमों की कटु आलोचनामें लीन रहते हैं। वैसे भी लोकतांत्रिकक दौर के भारतीय समाज की एक धारा रही है। शुरू में वह पदधारकों का शुरू में स्वागत करता है, बाद में उसका विरोधी हो जाता है। लेकिन वही शख्सियत जब इतिहास में समाहित हो जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ समाज उसका घोर प्रशंसक हो जाता है। बीजेपी की ही राजनीति का उदाहरण इस संदर्भ में ले सकते हैं। एक दौर में बीजेपी विरोधियों की नजर में अटल उदार थे, जबकि आडवाणी कट्टर। लिहाजा आडवाणी लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे। लेकिन जैसे ही अटल युग की समाप्ति हुई और मोदी युग की ओर बीजेपी बढ़ चली, आडवाणी उन्हीं विरोधियों की नजर में आदर के पात्र होते गए और मोदी के कटु आलोचकों की संख्या बढ़ती गई। कुछ इसी अंदाज में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई अन्य नेता उभरा तो हो सकता है कि मोदी बीजेपी विरोधियों की नजर में ही प्रशंसा का पात्र बन जाएं और बीजेपी का भावी नेता आडवाणी और मोदी की तरह आलोचनाओं के केंद्र में आ जाए। सत्ता की राजनीति में मोदी की यात्रा पर निगाह डालते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती खुद की स्वीकार्यता बढ़ाना रही। जिस तरह चौथाई सदी से वे सत्ता के केंद्र में हैं, उसे देख कह सकते हैं कि इसमें वे कामयाब रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सबसे ज्यादा समय तक सत्ता को खुद के इर्द-गिर्द केंद्रीकृत करने में भी सफल रहे हैं। आज भारत की केंद्रीय सत्ता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उन्हीं के इर्द-गिर्द केंद्रित है और उन्हीं से शक्ति ग्रहण करता है।यह मोदी का दुर्भाग्य रहा कि उनके गुजरात की सत्ता संभालने के महज छह महीने बाद ही राज्य को गोधरा कांड के चलते भयानक सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा। गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में 1044 लोगों के मारे गए , जबकि 2548 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 223 लोग लापता बताए गए। दंगों के सात साल बीतने के बाद सरकार के ही अनुसार, लापता लोगों की संख्या कुछ बढ़ गई। इन दंगों के बाद नरेंद्र मोदी विशेषकर कांग्रेस और वामपंथी दलों के निशाने पर आ गए। देश के वामपंथी सोच से प्रभावित स्वयंसेवी संगठनों ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा खोल दिया। एक तरह से मोदी को राजनीतिक घृणा का पात्र बनाने की कोशिश

ऑन लाइन ट्यूटरिंग का कारोबार काफी फायदेमंद होता है. किसी भी विषय पर अच्छी जानकारी के बाद ही इस काम को शुरू किया जा सकता है. इसमें स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन की भांति पढ़ाई करते हैं. बस, अंतर इतना ही होता है कि स्टूडेंट और ट्यूटर आमने-सामने नहीं होते बल्कि एक-दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं.



ऑनलाइन टीचिंग में कमाई के ऑप्शन

आप घर बैठे ही देश अथवा विदेश में भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं. ऑन लाइन ट्यूटरिंग का कारोबार काफी फायदेमंद होता है. किसी भी विषय पर अच्छी जानकारी के बाद ही इस काम को शुरू किया जा सकता है. इसमें स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन की भांति पढ़ाई करते हैं. बस, अंतर इतना ही होता है कि स्टूडेंट और ट्यूटर आमने-सामने नहीं होते बल्कि एक-दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं.

इसमें अध्ययन सामग्री और आंकड़ों का आदान-प्रदान कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है. इस तरह की पढ़ाई मुख्य रूप से मैथ्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, अंग्रेजी, हिन्दी या फिर किसी विदेशी भाषा के लिए की जाती है. इसके अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं को केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहा जाता है.

योग्यता

वैसे तो टीचिंग के कारोबार में जाने के लिए बीएड, एमएड, पीएचडी के साथ टीईटी, नेट आदि परीक्षा पास करनी होती है लेकिन ऑन लाइन ट्यूटर्स के लिए ज्यादातर कंपनियां मास्टर डिग्रीधारकों को ही प्रमुखता देती हैं. इसके लिए भाषा का अच्छा ज्ञान और विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. व्यक्तिगत गुण टीचिंग के प्रति पैशन होना जरूरी है. भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. जिस भी देश के स्टूडेंट को ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना होता है, उन्हें पाठ्यक्रम, उनके सीखने का तरीका और अन्य जानकारी होनी जरूरी है. करेंट सिलेबस से अपने आपको अप-टू-डेट रखना जरूरी है. ऑनलाइन ट्यूटर्स के पास अपना कंप्यूटर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, माइक्रोफोन, हेडफोन, डिजिटल पेन, कंप्यूटर अटैच इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या शेयर स्क्रीन व वेब कैमरा वीडियो चैट के लिए होना जरूरी है.

रोजगार

ऑनलाइन ट्यूटरिंग को ई-ट्यूटरिंग भी कहा जाता है. इसकी मांग प्रत्येक ट्रेनिंग कंपनियों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होती है जहां पर ऑनलाइन क्लासेज चलाई जाती हैं. इसमें कुछ हद तक पार्टटाइम और कुछ लोग स्थायी रूप से भी काम करते हैं. कुछ कंपनियां घर से भी काम करने की आजादी देती हैं. इसमें समयावधि के लिए कोई भी सीमा नहीं होती है. लोग अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करा सकते हैं. इसमें महिलाओं और रिटार्यड लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.

कैसे प्राप्त करें जॉब

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्विस सेंटर पर अप्लाई करना पड़ता है. फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू और आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कंडीडेट का चुनाव किया जाता है. ज्यादातर कंपनियां ऐसे ट्यूटर्स हायर करती हैं जो लैंग्वेज स्किल्ड, एक्सेंट एक्सपर्ट और प्रोफेशनल कोर्स में महारथ होते हैं. जो कंपनियां इस तरह के सेंटर चलाती हैं वे सारी जिम्मेदारियां जैसे स्टूडेंट्स, उनका लेटेस्ट सिलेबस, टाइमटेबल और कोर्स का ट्यूटर्स भी वही निर्धारित करती हैं.

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन ट्यूटर्स की मांग होती है. प्राइवेट कंपनियों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ट्यूटर्स की मांग होती है. अच्छे अनुभव के आधार पर स्वयं का ट्यूटरिंग सेंटर खोला जा सकता है. ऑनलाइन सेमिनार, वर्कशॉप आदि के लिए भी अच्छी-खासी मांग होती है.

इस रोजगार में आमदनी बहुत ज्यादा होती है. घंटे के आधार पर आमदनी तो होती ही है. साथ ही, एक्स्ट्रा वर्क के भी पैसे मिलते हैं. इसके अलावा, मासिक सैलरी पर भी ट्यूटर्स हायर किए जाते हैं.

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सुनहरे भविष्य की राह

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ऐसे पेशेवर होते हैं जो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चरल डिजाइन, सिस्टम का कॉमन लेआउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं. ये प्रोफेशनल्स इनफॉर्मेशन सिस्टम में बिजनेस प्रोसेस को समझते हुए आर्किटेक्चर को डिजाइन में रणनीतिक रूप में तैयार करते हैं.

आज की दुनिया में हमारे अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो हवाई यातायात के नियंत्रण से लेकर मोबाइल फोन तक में मौजूद रहता है. ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आज सॉफ्टवेयर के कारण ही वजूद में हैं. यहां तक की अब पब्लिक फाइनेंस और रिटेल सेक्टर भी सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो चुके हैं. इस तरह की कंपनियों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए हमेशा उन्नत और सस्ते सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का आर्किटेक्चर इन सभी बातों पर खासा असर डालता है. यही वजह है कि वर्तमान में करियर के रूप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लोगों की खास पसंद बनते जा रहे हैं. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ऐसे पेशेवर होते हैं जो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चरल डिजाइन, सिस्टम का कॉमन लेआउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं. ये प्रोफेशनल्स इनफॉर्मेशन सिस्टम में बिजनेस प्रोसेस को समझते हुए आर्किटेक्चर को डिजाइन में रणनीतिक रूप में तैयार करते हैं.

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में फर्क

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों प्रोफेशनल्स एक ही क्षेत्र यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में काम करते हैं. हालांकि वे एक ही क्षेत्र में काम करते हैं फिर भी दोनों की जॉब प्रोफाइल कई मायनों में भिन्न होती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न टास्क के लिए डिजाइनिंग, कोडिंग औ रसॉफ्टवेयर के निष्पादन के कार्य होते हैं जबकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर के संपूर्ण डेवलपमेंट का डिजाइन तैयार करता है लेकिन उनके कार्यक्षेत्र में कोडिंग शामिल नहीं होती. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट्स से बात करके उनकी आवश्यकताओं को समझता है वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन का पालन करना होता है.

योग्यता - सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए कैंडीडेट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन के बाद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पैकेज की पढ़ाई करनी होती है. इस क्षेत्र से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता करता है. किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जरूरी है कि वह नये सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेज से अप-टू-डेट रहे. सफलता के लिए 10+2 की पढ़ाई मान्यता प्राप्त बोर्ड से करें. इसके बाद कम्प्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कोर्स कम्पलीट करें. उस सॉफ्टवेयर पैकेज में शामिल हों जिसे पढ़ने और उस क्षेत्र में काम करने में दिलचस्पी रखते हों.

संभावनाएं - सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में कैंडीडेट कम्प्यूटर, आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से संबंधित सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी में अवसर पा सकता है. अगर कैंडीडेट के पास सॉफ्टवेयर डिजाइन और एनालिसिस में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो और भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं. आर्किटेक्ट चाहे तो सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट्स, आईटी इंडस्ट्री के साथ ही कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर में भी रोजगार पा सकते हैं. ऐसे क्षेत्र जिनमें एप्लीकेशंस और मोबाइल डिवाइस भी शामिल हैं, में दिन-ब-दिन बढ़ते सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की मांग के कारण सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के सामने ढेरों विकल्प मौजूद हैं. इस क्षेत्र में सफलता के लिए कैंडीडेट में क्रिएटिविटी, कस्टमर सर्विस स्किल, विश्लेषण और समस्याओं को समाधान करने की क्षमता बेहद जरूरी है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा भी अतिरिक्त लाभ देता है. यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें वेतन भी उच्च स्तर का मिलता है.

वेतन - एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सालाना आय औसतन 10,00,000 रुपये तक हो सकती है जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की 12,50,000 रुपये सालाना कमाई हो जाती है. उच्च शिक्षा का विकल्प सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कम्पिटीटिव क्षेत्र है, लेकिन इसमें उच्च शिक्षा हासिल करने पर कैंडीडेट्स को वरीयता मिलती है. कैंडीडेट चाहे तो खुद को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में नामांकन करके सर्टिफाइड डेवलपर बन सकता है.

व्यक्तिगत योग्यता

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट वह होता है जो भिन्न-भिन्न सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पढ़ता है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का काम करता है. सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेज की अच्छी जानकारी के साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को इंटैलेक्चुअल नॉलेज की भी जरूरत होती है जिससे वह सॉफ्टवेयर डिजाइन बना सके. करियर की शुरुआत करने के बाद भी उन्हें नये लैंग्वेजेज पढ़ते रहने की जरूरत होती है.

संस्थान

पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी
मेघालय कालीकट यूनिवर्सिटी, केरल

आइआइएम में दाखिला लेने का सपना देखनेवाले अभ्यर्थियों के लिए समय आ गया है कि वे परीक्षा के लिए कमर कस लें. कैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सावधानी से पूरी कर रणनीति के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाएं.



एक्यूरेसी से ही मिलेगी कैट में कामयाबी

कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है. कैट 2013 के आयोजन की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर के पास है. पिछले वर्ष हुई दिक्कतों के मद्देनजर इस बार कंप्यूटर बेस्ड पेपर की सुरक्षा और बढ़ा दी गयी है. 5 अगस्त से इसके वाउचर मिलने लगे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि एक्यूरेसी ही इस परीक्षा में कामयाबी का मूल मंत्र है.

कैट कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. साल में एक बार होनेवाली इस परीक्षा से विभिन्न आइआइएम के अलावा कई नामी-गिरामी संस्थानों में मैनेजमेंट के कोसरें में दाखिला होता है. एमबीए करने की इच्छा रखनेवाले अभ्यर्थियरें के लिए आइआइएम सर्वोत्तम विकल्प है. यहां दाखिला पाने की पहली सीढ़ी है कैट. इस कंप्यूटर लिखित परीक्षा के बाद बारी आती है ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और साक्षात्कार की. आइये जानते हैं कैट 2013 के बारे में कुछ खास तथ्य, साथ ही यह भी कि इसमें कामयाबी के लिए किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.

योग्यता पर करें गौर

इस परीक्षा के लिए किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम योग्यता स्नातक है, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. स्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यदि उनके स्नातक के पहले दोनों वर्ष में कुल 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हों.

पेपर का स्वरूप

पेपर मुख्यता दो भागों में बंटा होता है. पहला भाग क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डेटा इंटरपेट्रेशन, दूसरा भाग वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का होता है. हर भाग में 30-30 प्रश्न होते हैं. दोनों भागों को हल करने के लिए 70-70 मिनट का समय दिया जाता है. इसके अलावा 15 मिनट का ट्यूटोरियल भी दिया जाता है. इसे छात्रों को कंप्यूटर और बाकी सिस्टम को समझने में देना चाहिए. विशेषज्ञों के मुताबिक यह समय बहुत कीमती होता है. इस दौरान छात्र खुद को मानसिक रूप से तैयार करें. इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है. इस प्रकार, यह परीक्षा कुल दो घंटे 35 मिनट की होती है, जिसमें ट्यूटोरियल का समय शामिल है.

एक भाग की परीक्षा एक बार में होती है. सभी 30 प्रश्न उसी भाग के होते हैं. इसे पूरी तरह खत्म होने के बाद ही अगले सेक्शन की परीक्षा आरंभ होती है. बिना एक भाग पूरा किये दूसरे में नहीं जा सकते और न ही एक बार एक सेक्शन सबमिट करने के बाद उसे दोबारा देख सकते हैं. पूरी परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं मिलता. रफ काम करने, जोड.ने-घटाने या दूसरे कायरें के लिए एक



स्क्रेच पेपर, इरेजर और पेंसिल सेंटर द्वारा दी जाती है. दो घंटे 35 मिनट का समय एग्जामिनेशन रूम में गुजारना अनिवार्य है. कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे समय एक टाइमर चलता है, जो यह बताता है कि परीक्षा खत्म होने में कितना समय रह गया है. इसे ऑन स्क्रीन टाइमर कहते हैं.

कैसे करें तैयारी

कैट अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जानी जाती है. बेहतर यह है कि तैयारी के दौरान पिछले वर्षों के पेपर देखें. उनसे अभ्यास करें. पहले से अलग अब कैट पास करने के लिए स्पीड की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी एक्यूरेसी की. प्रश्नों की संख्या कम कर दी गयी है, पर जरूरी है कि जो प्रश्न करें वे सही हों. चयन के लिए कम से कम दोनों भागों में से 22-23 उत्तर ठीक होने चाहिए. चयन परसेंटाइल के हिसाब से होता है. इसलिए अभ्यर्थी न सिर्फ अच्छा करें, बल्कि अपने समूह में दूसरों से अच्छे नंबर लाएं. याद रखें कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में चार विकल्प दिये होते हैं, जिनमें से एक सही होता है. हर सही उत्तर पर तीन अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर एक अंक कटता है. निगेटिव मार्किंग होने के कारण जो प्रश्न नहीं आएं उन्हें छोड. दें. विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा पास करने के लिए कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वहीं लॉजिक का भी अपना महत्व है. इस पेपर में गणित का टेस्ट न होकर लॉजिकल टेस्ट होता है. परीक्षा में गौर किया जाता है कि आवेदकों में समस्या सुलझाने की समझ है या नहीं. रीडिंग पर विशेष ध्यान दें. खूब पढे. और अभ्यास करें. अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री क्लियर रखें. पुराने कैट के पेपर देखें. ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें. समूह में पढ़ाई करें, ताकि यह जान पाएं कि बाकी उम्मीदवारों के बीच आप कहां खडे. हैं. प्रमुख अंगरेजी, हिंदी अखबारों के संपादकीय पढे.. इंटरनेट से जितना ज्यादा मुमकिन हो सके, अच्छे कंटेंट जुटाएं और उसे पढे.. अपनी तैयारी के लिए फंटलाइन, इंडिया टुडे और बिजनेस वर्ल्ड जैसी मैगजीन की मदद भी ले सकते हैं।

न्यूज इन शॉर्ट

राज्यपाल डेका ने की विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता इभानन साहू की सराहना

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता श्री इभानन साहू ने मुलाकात की। ऑटिज्म से प्रभावित आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर के इस 22 वर्षीय छात्र ने हांगकांग में आयोजित स्पेशल ओलंपिक ईस्ट एशिया रीजनल बॉलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राज्यपाल ने इभानन साहू की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की। श्री डेका ने कहा कि इभानन साहू की उपलब्धि अदम्य इच्छाशक्ति और कठोर परिश्रम का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी सफलता न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राज्यपाल ने आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्था के शैक्षणिक कार्यो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने स्वेच्छानुदान मद से 10 कम्प्यूटर प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन धबलिया, निदेशक डॉ. साधना नायक, प्राचार्य श्रीमती प्रतिष्ठा शुक्ला, एच.एफ.ओ. श्री नित्यानंद जैसवाल, इभानन की माता श्रीमती तेजश्री साहू एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

एनएमएमएस परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए विशेष तैयारी

उत्तर बस्तर कांकेर। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) परीक्षा 2026-27 में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन और परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए जिले में विशेष तैयारी की रणनीति बनाई गई है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशन में विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों की पहचान करने, विशेष कक्षाएं संचालित करने, नियमित अभ्यास कराने और साप्ताहिक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री रमेश कुमार निषाद एवं जिला मिशन समन्वयक (डीएमसी) श्री नवनीत पटेल के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की तैयारी की नियमित समीक्षा और निगरानी पर जोर दिया गया है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उन्हें अच्छे, मध्यम और कमजोर वर्गों में चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के कमजोर विषयों और पाठों की सूची तैयार कर नियमित समीक्षा की जाएगी। तैयारी के लिए अवधारणा समझने, उदाहरण हल करने, अभ्यास करने, परीक्षा देने, गलतियों का विश्लेषण करने और दोबारा अभ्यास करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाओं में आसान से कठिन स्तर तक के प्रश्न हल कराए जाएंगे, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों और समयबद्ध अभ्यास के माध्यम से तैयार किया जाएगा।एनएमएमएस परीक्षा शनिवार 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। विद्यालय स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित है। विद्यालयों द्वारा आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज संबंधित परीक्षा केंद्र में 27 अक्टूबर तक जमा किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन प्रविष्टि एवं आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि पात्र विद्यार्थियों के आवेदन समय-सीमा में पूर्ण कराएं, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी अवसर से वंचित न रहे।परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। पहला प्रश्नपत्र मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) का होगा, जिसमें 90 प्रश्नों के लिए 90 अंक निर्धारित हैं। इसका समय सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक रहेगा। दूसरा प्रश्नपत्र शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी) का होगा, इसमें भी 90 प्रश्नों के लिए 90 अंक निर्धारित हैं और परीक्षा दोपहर 01 बजे से 2.30 बजे तक होगी। एसएटी में गणित के 20, विज्ञान के 35 और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे। उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संवेदनशील राहत व्यवस्था, दुर्घटना प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल

जशपुर जिले में 16 मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रत्येक प्रभावित परिवार को मिलेगी 4 लाख रुपये की सहायता, कठिन समय में परिजनों को राहत देने की पहल

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और उन्हें आर्थिक संबल देने की इसी पहल के तहत जशपुर जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 16 व्यक्तियों के निकटतम वारिसों के लिए कुल 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप समय पर सहायता मिल सके। किसी परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न दुख और क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जीवन को पुनः व्यवस्थित करने में सहायक होती है।कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत 16 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इन प्रकरणों में कुएं, तालाब, नदी, बांध एवं अन्य जलस्रोतों में डूबने से हुई मृत्यु के मामले शामिल हैं। शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत पात्र निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिले के विभिन्न विकासखंडों के 16 प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता

जारी आदेश के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम बेमतातोली में मनीषा बाई की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ललकू राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जशपुर तहसील के ग्राम बाहमनपुर में बीकांत तिर्की की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री बरनाबास तिर्की के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। फरसाबहार तहसील के ग्राम सिंगिबहार में सरस्वती बाई की तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री अनूप राम के आवेदन पर भी 4 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।मनोरा तहसील के ग्राम पटिया (अंगराकटोना) में लच्छू राम की बांध के पानी में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री मधुरा राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा ग्राम रेमने में बलदेव राम की ईब नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीमती जगमाईत बाई के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार तपकरा तहसील के ग्राम साजबहार (कंडरापानी) में शबनम तिग्गा की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री संतोष तिग्गा के आवेदन पर 4 लाख रुपये तथा मनोरा तहसील के ग्राम लिटिम में मोनिका एक्का की कुएं में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ओंकार एक्का के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।फरसाबहार तहसील के ग्राम कोनपारा में नरेन्द्र डनसेना की डेम के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्रीस्वीकृत किए गए हैं।

डिजिटल माध्यमों से छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को दुनिया तक पहुंचाएं: राज्यपाल रमेन डेका



डिजिटल माध्यमों से छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को दुनिया तक पहुंचाएं- राज्यपाल श्री रमेन डेका

खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककलाओं जैसे पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, कर्मा और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराओं का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश की इस सांस्कृतिक थाती को मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश-विदेश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए। राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय का 70वां स्थापना दिवस समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 70 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक योगदान का परिणाम बताया।

राज्यपाल श्री डेका ने दानवीर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा सिंह की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संगीत मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है, जबकि नृत्य, चित्रकला और शिल्प समाज के इतिहास व संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि कला के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ-साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण बहुत जरूरी है। साथ ही, उन्होंने कला को आजीविका और व्यवसाय से जोड़ने की संभावनाओं पर भी बल दिया।

सांसद श्री संतोष पांडे ने राजपरिवार के योगदान को बताया अनुकरणीय

सांसद श्री संतोष पांडे ने कहा कि राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री की स्मृति में दिया गया दान अद्वितीय और अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जमीन दान करना भी कठिन है, लेकिन राजपरिवार की दूरदर्शी सोच ने खैरागढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने शिक्षा, कला-कौशल, परिश्रम और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनकल्याणकारी योजना बनी सहारा

पूजा पटेल को मिला मातृत्व और बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए आर्थिक संबल

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

मां के लिए अपने बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और उज्ज्वल भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई बार जरूरतमंद परिवारों के लिए बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौती बन जाता है। ऐसे परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर मातृ एवं शिशु कल्याण की दिशा में सार्थक पहल साबित हो रही है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम सारबहरा की निवासी श्रीमती पूजा पटेल भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। श्रम विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत मिली 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस राशि का उपयोग वे अपने बच्चे के पौष्टिक आहार और बेहतर देखभाल के लिए कर रही हैं।



20 हजार रुपये की सहायता से बच्चे के बेहतर पोषण की राह हुई आसान

ग्राम सारबहरा निवासी श्रीमती पूजा पटेल के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। श्रम विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि से उन्हें अपने बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। इस आर्थिक सहयोग से वे बच्चे के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर पा रही हैं।

बच्चे के शुरुआती जीवन में उचित पोषण और देखभाल उसके स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे समय में शासन से मिली आर्थिक सहायता पूजा पटेल के लिए उपयोगी साबित हो रही है। इससे उन्हें अपने बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देने और उसकी बेहतर देखभाल करने में सहयोग मिल रहा है।

मातृत्व की जिम्मेदारियों में आर्थिक सहयोग दे रही महतारी जतन योजना

छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना का उद्देश्य पात्र पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि माताओं को प्रसव के बाद अपनी तथा नवजात शिशु की देखभाल और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।

विशेष रूप से सीमित आर्थिक संसाधनों वाले श्रमिक परिवारों के लिए यह सहायता महत्वपूर्ण होती है। मातृत्व के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और बच्चे की देखभाल के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता परिवारों की वित्तीय परेशानियों को कुछ हद तक कम करने में सहायक बनती है।

पूजा पटेल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने से उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

बच्चे के पोषण के लिए मिली मदद से पूजा के चेहरे पर आई खुशी

श्रीमती पूजा पटेल ने बताया कि मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत मिली 20 हजार रुपये की सहायता राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस राशि से उन्हें अपने बच्चे के पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने में आर्थिक सहयोग मिला है। इससे वे बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण पर बेहतर ध्यान दे पा रही हैं।

उन्होंने कहा कि शासन की इस योजना से उन्हें मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने में आर्थिक सहारा मिला है। सहायता राशि प्राप्त होने से बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिल रही है। यह सहयोग उनके परिवार के लिए राहत का माध्यम बना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभार

मिनीमाता महतारी जतन योजना से लाभान्वित श्रीमती पूजा पटेल ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दी गई 20 हजार रुपये की सहायता राशि से उन्हें अपने बच्चे के बेहतर पोषण और देखभाल में मदद मिल रही है।

पूजा पटेल ने योजना को जरूरतमंद माताओं के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार की आर्थिक सहायता से महिलाओं को मातृत्व के दौरान संबल मिलता है और वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाती हैं।

मातृ एवं शिशु कल्याण की दिशा में सार्थक पहल

मिनीमाता महतारी जतन योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का माध्यम नहीं, बल्कि जरूरतमंद माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं को मातृत्व के दौरान आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करती है।

'सुकमा कनेक्ट 2.0' को मिली राष्ट्रीय पहचान, देश के 14 चयनित प्रस्तावों में

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अंतिम छोर तक नागरिक सेवाएं पहुंचाने की पहल को मिली नई गति

24 घंटे बहुभाषी कॉल सेंटर और मोबाइल सेवा वैन से घर के करीब मिलेंगी नागरिक सुविधाएं

सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप दूरस्थ वनांचलों तक पहुंचेगा प्रशासन, परियोजना के लिए 1.17 करोड़ रुपए मंजूर

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों तक शासन की योजनाओं और नागरिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सुकमा जिले की अभिनव पहल 'सुकमा कनेक्ट 2.0' को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 'स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव' के तहत देश के 14 चयनित प्रस्तावों में शामिल करते हुए 1.17 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। प्रशासन द्वारा समन्वय केंद्र सेवा का विस्तार करते हुए प्रस्ताव ÷सुकमा कनेक्ट (सीएमसीसी) 2.0÷ प्रस्तुत किया गया था। सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप अंतिम छोर तक शासकीय सेवाएं पहुंचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत अब दूरस्थ गांवों के ग्रामीणों को मोबाइल सेवा वैन और चौबीसों घंटे संचालित बहुभाषी कॉल सेंटर के माध्यम से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।



मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में शासकीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से भी नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में 'सुकमा कनेक्ट 2.0' तकनीक और प्रशासनिक समन्वय के जरिए ग्रामीणों को जरूरी सेवाएं उनके गांवों के करीब उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा।

'40 हजार से अधिक फोन कॉल, हजारों नागरिकों तक पहुंची सेवाएं'

सुकमा जिले में मार्च 2026 से संचालित केंद्रीकृत निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र (सीएमसीसी 1.0) के माध्यम से अब तक 40 हजार से अधिक फोन कॉल किए गए हैं। इस पहल के तहत 10 हजार 78 आयुष्मान कार्ड और 11 हजार 103 नए मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 हजार 788 आधार नामांकन और 27 हजार 391 बायोमेट्रिक अपडेट किए गए हैं। आजीविका संवर्धन के लिए 452 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन कर 4 हजार 745 परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।

'स्थानीय बोलियों में मिलेगी सहायता, गांव-गांव पहुंचेंगी मोबाइल सेवा वैन'

'सुकमा कनेक्ट 2.0' के तहत स्थानीय बोलियों में चौबीसों घंटे सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहुभाषी कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। दो मोबाइल सेवा वैन दूरस्थ गांवों में पहुंचकर आधार सहित अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम होगी।

198 आवासीय विद्यालयों और आश्रमों में होगी डिजिटल निगरानी'

परियोजना के तहत शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को भी सुदृढ़ किया जाएगा। जिले के 198 आवासीय विद्यालयों एवं आश्रमों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही शाला से बाहर बच्चों की पहचान और निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ा जा सके। नागरिक सेवाओं, शासकीय योजनाओं और शिक्षा संबंधी गतिविधियों की एकीकृत निगरानी के लिए कलेक्टर स्तर पर डिजिटल डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और सेवाओं की उपलब्धता की निगरानी एक ही मंच से हो सकेगी। यह पहल सुकमा में दूरस्थ आदिवासी अंचलों में ÷टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड लास्ट-माइल गवर्नेंस÷ का उदाहरण सामने लेकर आएगी।

एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अभिषेक शर्मा** द्वारा 202, भाटागांव चौराहा , रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन 492015 से प्रकाशित एवं आसमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , गॉस मेमोरियल हाल के पास , जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित।

संपादक - रिज़वान आज़म, **समूह संपादक**- महेश कुमार तिवारी ईमेल - eksatbulletin@gmail.com R.N.I Number - CHHHIN/2020/78457 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार ।